हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 330 बेमेतरा, रविवार 26 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

समाचार सार

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे में 48% की भारी गिरावट

नईदिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उनका एकीकृत शुद्ध लाभ 48 प्रतिशत घटकर 1,783 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने बताया कि लाभ में ये बड़ी गिरावट संयुक्त अरब अमीरात के एनएमसी ग्रुप मामले में अदालत के बाहर हुए समझौते के तहत 5,680 करोड़ रुपये के भुगतान के कारण दर्ज की गई।

14 घंटे तक बंद रहेंगी आधार की ऑनलाइन सेवाएं

नईदिल्ली। आधार ने ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। आधार ने 24 जुलाई को भेजे एक नोटिफिकेशन में बताया कि 25 जुलाई को आधार की ऑनलाइन सेवाएं अस्थाई तौर पर बंद रहेंगी। अगर आपको भी आज आधार से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो आपके पास शाम 7 बजे तक का समय है। आधार द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, एजेंसी के पूरे सिस्टम का मेनटेनेंस किया जाना है।

बॉडी कैमरा लगाकर ड्यूटी करेंगे टीटीई

नईदिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन ने बॉडी वॉर्न कैमरा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस नए सिस्टम के तहत, टिकट चेकिंग कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर टिकट की जांच करेंगे, जिससे टिकट जांच के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि रिकॉर्ड होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट उत्तर मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर नरेश पाल सिंह के खास निर्देशों के बाद 24 जुलाई से शुरू की गई है। पहले चरण में प्रयागराज मंडल की दो प्रमुख प्रीमियम ट्रेनों प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रमशक्ति एक्सप्रेस में ड्यूटी करने वाले टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 की मौत

कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा से लगे सलोरा छुरी गांव में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली (ए)। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद और पिछले कई हफ्तों से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। मेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही थी और इस इस्तीफे को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि, पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और अपने फैसले पर अड़ी रही। आज सरकार और सीजेपी के तीसरे दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा सौंपा है।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा किया पत्र- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का पत्र जारी किया। जिसमें उन्होंने लिखा- मेरे युवा साथियों, मैं पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

देश के युवाओं की अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं- उन्होंने कहा, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं।

नीट पेपर लीक पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?- उन्होंने आगे लिखा, तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तारीख की घोषणा की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया।

री-नीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा?पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए।

इसके लिए पूरी सरकार का समन्वित दृष्टिकोण के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, खासकर जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा, साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई।

धर्मेंद्र प्रधान बोले- छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे- पहले ही दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे लिखा, 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली।

आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों देना पड़ा इस्तीफा?- केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पिछले कई हफ्तों से बन रहा भारी सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव था। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा की शुचिता से समझौता होने के आरोपों को लेकर देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच और कानूनी कार्रवाई पहले से ही चल रही है। विरोधियों और छात्र संगठनों का आरोप था कि केंद्र सरकार परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने और छात्रों की चिंताओं का समय पर समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके बाद उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा।

यह लोकतंत्र की जीत है: सोनम वांगचुक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाने-माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि, सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर 20 दिन तक अनशन किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनाम वांगचुक ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- यह लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र... जो सड़कों से निकला है। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और देश की जेन जी को बधाई; और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्यागकर देश के हर कोने से आवाज उठाई। जवाबदेही से अब सुधार की ओर।

सीजेपी का आंदोलन खत्म करने का एलान, कहा- सरकार ने मान ली मांगें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को अपना आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने का बड़ा एलान किया। यह घोषणा केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद हुई। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सीजेपी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के सौरव दास शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का तीसरा दौर सकारात्मक रहा। वार्ता के तुरंत बाद सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी ने देश भर से आए प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की है।

सौरव दास ने सरकार से बातचीत की सारी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग यह थी कि

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर न केवल दिल्ली में बल्कि सभी भाजपा-शासित और भाजपा-सहयोगी राज्यों में वापस ली जानी चाहिए। यह हमारी दूसरी मांग थी। सरकार ने उस मांग को भी मान लिया है। साथ ही, इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह दर्ज सभी एफआईर की कॉपी शेयर करेगी। हमारी आखिरी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 15 से 20 एफआईआर दर्ज की गई थीं और हमें किसी भी हाल में तीन से चार दिनों के भीतर वे कॉपी मिल जाएंगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। इसे समझते हुए, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो एक लिखित गारंटी है। सरकार ने कहा है कि वह मंगलवार तक इसे हमारे साथ शेयर करेगी। हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन एफआईआर और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार की गारंटी मिल जाएगी।

पीएम से मेरी बातचीत का नतीजा: शरद पवार

मुंबई। केंद्र सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य दो मांगें मान लिए जाने के बाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शन खत्म करने का एलान कर दिया है। इस बीच एनसीपी (एसपी) के नेता शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। शरद पवार ने दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की वजह बनी। शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने दावा किया कि इसी चर्चा के नतीजे के तौर पर शिक्षा मंत्री ने आज इस्तीफा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) नेता शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि यह देश की युवा शक्ति की बड़ी जीत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की मांग पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होकर और दमन से न डरते हुए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।

पीएम मोदी मांगे माफी; छात्रों पर हिंसा के लिए अमित शाह जिम्मेदार: राहुल गांधी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से आंदोलन समाप्ति के एलान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, उस पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमले किए गए हैं, उस पर कब्जा कर लिया गया है और उसका निजीकरण कर दिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह देश के छात्रों की जीत है और शिक्षा प्रणाली की रक्षा की एक बड़ी प्रतिक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो शिक्षा प्रणाली कभी भारत की शान हुआ करती थी, उस पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमले हो रहे हैं, उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है और उस पर वैचारिक कब्ज़ा जमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निवर्तमान शिक्षा मंत्री को इस प्रशासनिक नाकामी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था के विनाश का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका जाना सही कदम है, लेकिन समस्या केवल एक व्यक्ति के हटने से खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि संघ भी उतना ही जिम्मेदार है। शिक्षा व्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है और इसे ठीक करने के लिए कड़े व बुनियादी कदम उठाने की ज़रूरत है।

धर्मेंद्र प्रधान को वापस लेना चाहिए इस्तीफा: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव

दुर्ग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि एक विभाग में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि उसके विभाग में इस तरह से पेपर लीक हो। गजेंद्र यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पुरानी मैकाले शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लाने में धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया जाना चाहिए।

रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड 5 अगस्त तक बढ़ी

जेल जाने से पहले भूपेश बघेल ने की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ाई।

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट पहुंचे और जेल भेजे जाने से पहले रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय व राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

EOW और ED के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल पर शराब घोटाले, कोल लेवी (कोयला लेवी) और कस्टम मिलिंग से जुटाए गए अवैध पैसों को

ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े 52 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में देवेंद्र डड़सेना की भूमिका रही है। रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र डड़सेना से करीब तीन घंटे तक संयुक्त पूछताछ की गई थी, लेकिन रामगोपाल किसी भी तरह की राशि के ट्रांसफर से इनकार किए। जांच एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटालों से जुड़े करीब 800 करोड़ रुपये इधर-उधर ट्रांसफर किए गए। हालांकि रामगोपाल अग्रवाल इन सभी आरोपों को खारिज किए थे।

शराब कारोबार में 3,400 करोड़ का हुआ है घोटाला : जांच एजेंसी- कोयला घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में वे न्यायियक रिमांड पर थे। आज रिमांड खत्म होने पर रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें कि रविवार को जांच एजेंसी रामगोपाल अग्रवाल को सेंट्रल जेल ले गई थी, जहां शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब कारोबार में करीब 3,400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

महामाया पहाड़ में युवती का मिला कंकाल, शिनाख्त के प्रयास जारी

अंबिकापुर। अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पर शनिवार को युवती का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. शव का कुछ हिस्सा पेड़ पर लटका हुआ था. घटना स्थल से कपड़े, ब्रेसलेट और दवाईयां भी मिली है. हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, महामाया पहाड़ पर वनकर्मी ने पुरानी लाश को पेड़ पर लटका हुआ देखा. एक हिस्सा पेड़ से लटका हुआ था, तो धड़ नीचे गिरा हुआ था सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. शव की हालत देखकर फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया।

भारतीय डाक और फ्लिपकार्ट के बीच हुई अहम साझेदारी

दूर-दराज के इलाकों में पार्सल पहुंचाएंगे डाकिए

नईदिल्ली (ए)। भारत के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए पार्टनरशिप की है। देश में दूर-दराज के इलाकों में डिलीवरी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

शुक्रवार को दिल्ली में डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग

की बेजोड़ पहुंच और भरोसेमंद डिलीवरी नेटवर्क के साथ-साथ भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाकर पूरे देश में कुशल, विश्वसनीय और ग्राहक-केंद्रित पार्सल डिलीवरी समाधान प्रदान करना है। समझौते के तहत, डाक विभाग पूरे भारत में फ्लिपकार्ट शिपमेंट के लिए अंतिम दूरी तक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करेगा। फ्लिपकार्ट, दूर-दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। इन सेवाओं में प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी पार्सल की डिलीवरी, ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रमाणीकरण और रियल-टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग शामिल हैं। ये समझौता कुशल पार्सल आवागमन और वितरण के लिए तेज डिलीवरी, बेहतर परिचालन समन्वय और निर्बाध प्रौद्योगिकी एकीकरण पर केंद्रित है। इस सहयोग से भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को समर्थन देने वाले लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के माध्यम से, फ्लिपकार्ट को डाक विभाग के 1.6 लाख से ज्यादा डाकघरों के विशाल नेटवर्क और पूरे भारत में अद्वितीय वितरण नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे बाजार तक व्यापक पहुंच, वितरण दक्षता में सुधार और विशेष रूप से दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। बताते चलें कि इससे पहले अमेजन इंडिया ने दूर-दराज के इलाकों में सामानों की डिलीवरी पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की थी।

प्रियंका गांधी का पीएम पर निशाना

वायनाड (ए)। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्होंने हिम्मत, साहस, जिम्मेदारी और नेतृत्व दिखाना होगा।

उन्होंने कल्डी में भूस्खलन स्थल का पहली बार दौरा किया, जहां इस आपदा में आठ लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्होंने हिम्मत, साहस, जिम्मेदारी और नेतृत्व दिखाना होगा। कांग्रेस सांसद सुबह कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे और सड़क मार्ग से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के मेप्पडी में भूस्खलन स्थल की ओर रवाना

हुए। आपदा स्थल की ओर जाते समय, वाड्रा का स्वागत वायनाड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह छात्रों नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली में छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद वह दोपहर करीब 2 बजे अनाक्कम्पॉयिल सुरंग सड़क परियोजना के पास आपदा स्थल पर पहुंची और कुछ बचे हुए लोगों से मिली, और उनसे सुना कि वे कैसे बाल-बाल बचे।

सूत्रों के अनुसार, वह घटना में घायल हुए उन लोगों से मिलने जाएंगी जिनका इलाज यहां डब्लूआईएमएस अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही उस स्थल का भी दौरा करेंगी जहां कांग्रेस चोरालमाला भूस्खलन के पीड़ितों के लिए घर बना रही है। 7 जुलाई को अनाक्कम्पॉयिल-मेप्पडी सुरंग परियोजना के स्थल पर हुए भूस्खलन में आठ लोगों की मौत हो गई, जिसका उद्देश्य वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ना है।

सरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 103 बोतल कोरेक्स के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से हो रही थी तस्करी..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 103 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कोरेक्स सिरप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कोरेक्स सिरप के अलावा एक मोटरसाइकिल, एक कार और दो मोबाइल फोन सहित कुल 5,73,072 रुपये का सामान जब्त किया गया है।पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमीषा पाण्डेय तथा डीएसपी संतोषी ग्रेस के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 24 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा के सोहेला क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल में कोरेक्स सिरप लाकर सरिया क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एन.एल. राठिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम देवगांव स्थित एफसीआई गोदाम के पास घेराबंदी की। इस दौरान लाल रंग की हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया।तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल में रखी प्लास्टिक बोरी से 103 बोतल कोडीन फॉस्फेट एवं ट्राईप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कोरेक्स सिरप बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह खेप कंटगपाली निवासी नरेश साहू के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 103 बोतल कोरेक्स सिरप (कीमत 23,072 रुपये), हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, एक सफेद अर्टिगा कार तथा दो मोबाइल फोन जब्त किए। तीनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) एवं 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।गिरफ्तार आरोपी1. गणेश पटेल (24), निवासी ग्राम बार, थाना सरिया 2. नरेश साहू (31), निवासी कंटगपाली, थाना सरिया 3. राजकुमार साहू (35), निवासी खैरा, थाना डोंगरीपाली, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एन.एल. राठिया, सउनि सुमन कुमार चौहान, प्रधान आरक्षक विजय यादव, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र सिदार, प्रधान आरक्षक अनिल साहू, प्रधान आरक्षक मोहन लाल गुप्ता, प्रधान आरक्षक टीकाराम पटेल, आरक्षक दिलीप स्नेही, आरक्षक श्रवण टंडन, आरक्षक ताराचंद मिरेन्द्र, आरक्षक मुकेश कश्यप, आरक्षक सुरेन्द्र पटेल, आरक्षक दिगम्बर पटेल, आरक्षक नर्मदा प्रसाद यादव तथा सायबर सेल से सउनि रामकुमार मानिकपुरी और आरक्षक कृष्णा डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी नेटवर्क से अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हैं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है।

भाजयुमो बरमकेला मंडल की संगठनात्मक बैठक संपन्न, सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

भारतीय जनता युवा मोर्चा बरमकेला मंडल की परिचयात्मक एवं संगठनात्मक बैठक शनिवार 25 जुलाई को संपन्न हुई। बैठक में नव नियुक्त मंडल प्रभारी पवन साहू एवं सह प्रभारी माधव पटेल का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ÷भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्यता अभियान 2026÷ को प्रभावी ढंग से संचालित करने, अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में भाजपा बरमकेला मंडल अध्यक्ष राज किशोर पटेल, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष जय किशन पटेल, भाजयुमो बरमकेला मंडल अध्यक्ष गोकुल विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री अजय पटेल, किशन साहू सहित मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।बैठक के अंत में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने, सदस्यता अभियान को सफल बनाने और युवाओं को भाजपा की विचारधारा से जोड़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मजदूर नेता ने दी प्रतिक्रिया

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:-कांकेर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के जिला अध्यक्ष सागर साहू ने इसे छात्रों युवाओं के संघर्ष का जीत बताया है। साहू ने बताया कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग पर एकत्रित हुए छात्रों युवाओं पर पुलुसी बर्बर हमला के बाद भी छात्रों युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर डेट रहे। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से विस्तारित होकर देश के कोने कोने तक फैल गया था। मजदूर नेता ने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के कारण देश के 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन मोदी सरकार इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया था। इस पेपर लीक हमारे देश के युवा समाज की भविष्य को पूरी तरह से अंधकारमय और अनिश्चितता की और धकेल दिया था। उन्होंने देश के सभी जनता को भी छात्रों युवाओं के साथ एकजुटता प्रकट और उनके आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है।

लीनेस क्लब सेवांजलि ने मनाया फाउंडर्स डे, संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्षों का हुआ सम्मान

स्मरण शक्ति बढ़ाने पर प्रेरक सत्र, अगस्त माह की सेवा गतिविधियों की बनी रूपरेखा

रायगढ़/मूक पत्रिका

लीनेस क्लब सेवांजलि द्वारा स्थानीय होटल ममता फाइन डाइन में फाउंडर्स डे (संस्थापक दिवस) हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में क्लब की संस्थापक अध्यक्ष लीनेस सुमिता पाण्डेय तथा पूर्व अध्यक्ष लीनेस लता बघेल एवं लीनेस रजनी मिश्रा का शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर माह में जन्मदिन मनाने वाली सदस्याओं का केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उन्हें पौधे भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान क्लब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) बैठक एवं सामान्य सभा आयोजित की गई। बैठक में आगामी आधिकारिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा अगस्त माह में आयोजित होने वाली विभिन्न सेवा गतिविधियों एवं क्लब कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।जीरो बजट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लीनेस रजनी मिश्रा ने ÷स्मरण शक्ति बढ़ाने÷ विषय पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने ट्राई मेमोरी एवं चैन मेमोरी जैसे रोचक खेलों के माध्यम से स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने की सरल एवं प्रभावी तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्याओं ने पूरे उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया।कार्यक्रम के समापन अवसर पर ली कावेरी शुक्ला, ली प्रतिभा सिंह, ली निशात अली, ली ममता चौहान, ली राजश्री शुक्ला, ली तनु शर्मा, ली बबली कुलवेदी, ली सरोजिनी कुर्रे, ली रूपांजलि देशमुख, ली रीता श्रीवास्तव, ली चंचला सिंह, ली प्रिया पाण्डेय एवं ली पूनम तिवारी सहित सभी सदस्याओं ने सेवा, मित्रता और समाजहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

फाउंडर्स डे का यह आयोजन क्लब की संस्थापक परंपराओं, सेवा भावना और संगठनात्मक एकजुटता का प्रतीक रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्याओं ने लीनेस क्लब सेवांजलि के उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर प्रगति की कामना की।

एक कॉल पर घर पहुंचेगा पौधा, वन विभाग की अनूठी पहल से हरियाली को मिलेगा नया विस्तार, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निःशुल्क पौधा वितरण वाहन को दिखाई हरी झंडी

फलदार, छायादार सहित अन्य प्रजातियों के पौधे होंगे उपलब्ध, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की वित्त मंत्री ने की अपील

निगम क्षेत्र में टोल-फ्री नंबर 8305186853 एवं 18002332631 पर कॉल कर अपने घर तक मंगवा सकेंगे निःशुल्क पौधे

रायगढ़/मूक पत्रिका

प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी रायगढ़ प्रवास के दौरान आज सुबह अपने निवास कार्यालय से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन मंडल रायगढ़ की अभिनव पहल के तहत निःशुल्क पौधा वितरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिक केवल एक टोल-फ्री नंबर 8305186853 एवं 18002332631 पर कॉल कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगवा सकेंगे। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ रायगढ़ अरविंद पीएम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि वन विभाग ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक बेहद सराहनीय व्यवस्था शुरू की है। कोई व्यक्ति अपने घर, आंगन, बाड़ी, बगीचे, खेत, तालाब किनारे या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पौधा लगाना चाहता है, तो उसे केवल वन विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल प्राप्त होने के बाद विभाग की टीम सीधे उसके घर पहुंचकर निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को पौधों के लिए नर्सरी या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण से जुड़ सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति के प्रति सम्मान और मातृऋण चुकाने का प्रतीक है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे, तो आने वाले वर्षों में रायगढ़ हरियाली की नई पहचान बन सकता है।

फलदार, छायादार सहित अन्य प्रजातियों के पौधों की होगी उपलब्धता-वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वन विभाग द्वारा इस योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार फलदार, छायादार एवं अन्य उपयोगी प्रजातियों के पौधे प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई अपने घर या खेत में आम, अमरूद, नींबू अथवा अन्य फलदार पौधे लगाना चाहता है, तो उन्हें भी प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण तभी सफल होगा जब अच्छे और स्वस्थ पौधे लोगों तक आसानी से पहुंचेंगे, और वन विभाग इसी उद्देश्य से यह सेवा शुरू कर रहा है।

हर नागरिक लगाए एक पेड़, हराभरा बने रायगढ़: वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी-वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां भी थोड़ी-सी जगह उपलब्ध हो-घर का परिसर, बगीचा, तालाब का किनारा, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थल वहां अवश्य पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि एक पेड़ केवल हरियाली नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पर्यावरण और बेहतर जीवन का आधार बनता है। उन्होंने नागरिकों से वन विभाग की इस जनहितैषी योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया

शिवसेना „ ने कहा छात्र-छात्राओं जंतर मंतर पर नीट पेपर लिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे यहां पुलिसिया लाठी चार्ज की कड़ी निंदा की

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शिवसेना ,क्ञ्ञ, पार्टी के छ, ग, प्रदेश महासचिव दाऊ राम चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय शर्मनाक और लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा प्रहार है चौहान ने कहा की इस कार्यवाही की कड़े शब्दों में भत्सर्ना करता है देश के लाखों मेघावी छात्र-छात्राएं बार-बार सामने आ रहे हैं पेपर लीक मामलों और भर्ती घोटाले के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित और आशंकित है वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी न्याय संगत मांगे सरकार के समक्ष रख रहे थे ऐसे में अन्नदाताओं और युवाओं की आवाज सुनने की बजाय, उन पर बल प्रयोग करना, आशु गैस के गोले छोड़ना और उन्हें जबरन खदेड़ना सत्ता के अहंकार को दर्शाता है शिवसेना पार्टी के प्रदेश महासचिव चौहान ने कहा देश के युवाओं और छात्रों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं लाठी चार्ज की इस घटना में कई छात्र गंभीर रूप से लहूलुहान होकर घायल हो गए हैं जो की बेहद पीड़ा दायक है जब देश के युवा अपनी जायज मांगों परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता दोषियों पर सख्त कार्यवाही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे तब सरकार ने संवाद स्थापित करने के बजाय दमन का रास्ता चुना लाठियां और गोलियों के दम पर युवाओं की आवाज को दबाने की यह कोशिश तानाशाही रवैयें को दर्शाती है लोकतंत्र में विरोध जताना हर नागरिक का मौलिक अधिकार हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने साबित कर दिया है की वहां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्य की भी हत्या कर रही है शिवसेना पार्टी ने राष्ट्रपति से मांग करती है, की प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्यवाही में गंभीर रूप से घायल हुए सभी छात्रों का मुक्त इलाज हो और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए नीट और अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएं चौहान ने कहा छात्र-छात्राओं द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कार्यो पर बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज करने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और प्रशासन पर तुरंत कार्यवाही की जाएं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें यदि सरकार ने छात्रों की मांगों को जल्द नहीं माना और अपना दमनकारी रवैया बंद नहीं किया तो शिवसेना, पार्टी द्वारा आंदोलन को पूरे देश में और अधिक तीव्र किया जाएगा जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी

क्षेत्र के बहुचर्चित बोंदा और कटंगपाली कोटवार नियुक्ति मामले में सामने आए नए तथ्य, विवाद ने पकड़ा तूल

बरमकेला/मूक पत्रिका

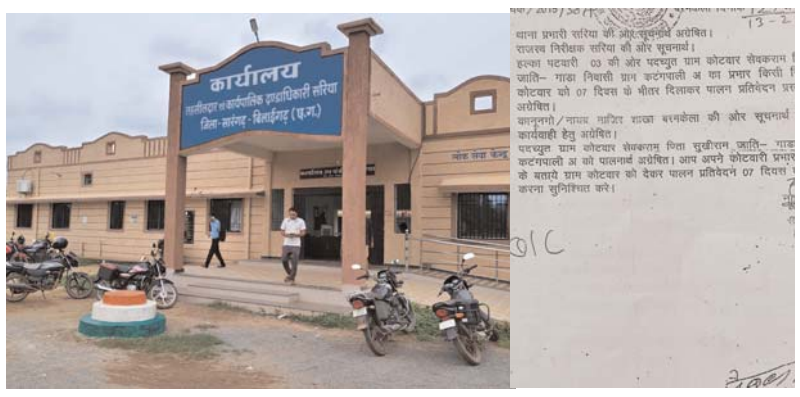

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत सरिया तहसील में बोंदा और कटंगपाली गांव की कोटवार नियुक्ति का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कोटवारी भूमि पर अवैध खनन के आरोपों के चलते दोनों गांवों के कोटवारों को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए कोटवारों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

शासन द्वारा कोटवारों को उनके जीवन-यापन के लिए कोटवारी भूमि प्रदान की जाती है। ऐसे में उक्त भूमि के दुरुपयोग या शासन के नियमों के विपरीत कार्य किए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, कटंगपाली गांव की कोटवारी भूमि पर अवैध खनन एवं उसके संरक्षण की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ से की गई थी। शिकायत के बाद तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए गए, जिसके तहत पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। जांच में कोटवारी भूमि पर खनन होने और बड़े गड्ढे पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के तहत संबंधित कोटवार को पद से बर्खास्त कर दिया गया।

बर्खास्तगी के बाद संबंधित कोटवार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार बोंदा गांव में भी कोटवारी भूमि पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर जांच उपरांत संबंधित कोटवार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे पद से हटा दिया गया।

नए कोटवार की नियुक्ति पर उठे सवाल

दोनों गांवों में नए कोटवारों की नियुक्ति के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कटंगपाली के पूर्व कोटवार गोविंद चौहान ने नए कोटवार की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सहित विभिन्न अधिकारियों को शिकायत भेजी है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि फ्लाई ऐश पटवाने से मना करने के कारण उन्हें पद से हटाया गया तथा नियमों की अनदेखी करते हुए उनकी पुत्री को प्राथमिकता नहीं दी गई और किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई।

वहीं बोंदा गांव में भी नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों द्वारा नियुक्त व्यक्ति को बाहरी निवासी बताया जा रहा है, जिससे गांव में विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई।

क्या कहते हैं नियम?

मिली जानकारी के अनुसार, भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के नियम (2) में बर्खास्त किए गए कोटवार के पारिवारिक सदस्यों को नियुक्ति नहीं दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। इसी नियम को लेकर वर्तमान नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

नए कोटवार ने क्या कहा?

बोंदा गांव में नियुक्त नए कोटवार डॉक्टर ने स्वयं को गांव का मूल निवासी बताया है। उनका कहना है कि उनके पास वर्ष 2015 में बरमकेला तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके पिता हलधर गांव के कोटवार रह चुके हैं तथा उनके परिवार के सदस्य चमरा और कुलधर भी पूर्व में इसी गांव में कोटवार के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऐसे में स्वयं को बाहरी निवासी बताए जाने के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है।

पूर्व नियुक्तियों पर भी उठ रहे सवाल

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोंदा के बर्खास्त कोटवार बेलाल (बेदलाल) कुर्रे मूल रूप से रैनभाठा, पुसौर के निवासी बताए जा रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं को डॉक्टर के पूर्वजों की वंशावली से संबंधित बताते हुए कोटवार पद की नियुक्ति प्राप्त की थी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा किया जाना शेष है।इसी प्रकार कटंगपाली के मामले में भी यह तथ्य सामने आया है कि गोविंदराम चौहान के पिता सेवकराम चौहान को वर्ष 2015 में कोटवारी भूमि पर अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने के बाद तत्कालीन तहसीलदार बरमकेला द्वारा पद से बर्खास्त किया जा चुका था। इसके बाद गोविंदराम चौहान की नियुक्ति को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

अब आगे क्या?

वर्तमान में बोंदा और कटंगपाली की कोटवार नियुक्ति का पूरा मामला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन इस विवाद का क्या समाधान निकालता है तथा नियुक्तियों को लेकर अंतिम निर्णय क्या होता है।तहसीलदार सरिया कोमल प्रसाद साहू ने कोटवार नियुक्ति विवाद पर बोले-नियुक्ति पूरी तरह नियमानुसार-बोंदा और कटंगपाली के कोटवार नियुक्ति विवाद को लेकर तहसीलदार सरिया कोमल प्रसाद साहू ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि दोनों पूर्व कोटवारों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत कदाचार के कारण पदच्युत (बर्खास्त) किया गया था।तहसीलदार के अनुसार, ग्राम कटंगपाली के पूर्व कोटवार गोविंद राम चौहान तथा ग्राम बोंदा के पूर्व कोटवार बेलाल कुर्रे ने शासकीय सेवा भूमि (कोटवारी भूमि) का कृषि कार्य के अतिरिक्त अवैध उत्खनन के लिए उपयोग किया था, जिससे शासकीय भूमि पर खदान एवं गड्ढे निर्मित हो गए थे।

NTPC लारा राख घोटाला: अफसरों का सिंडिकेट या राजनैतिक सरपरस्ती? 2025 की तरह फिर 'कार्रवाई का दिखावा', कब नपेगा NTPC का असली 'सफेदपोश' गैंग!

रायगढ़/मूक पत्रिका

एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसौर (रायगढ़) से निकलने वाली जहरीली फ्लाई एश (स्नद्य4, ह्यद्ध) के अवैध निपटान और कालाबाजारी का मामला अब राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक व राजनैतिक घोटाला बन चुका है। हाल ही में कोसमनारा और जोरापाली मोड़ के पास 235.84 मीट्रिक टन अवैध राख फेंकने पर ठोका गया ?3.53 लाख का जुर्माना महज एक 'आईवॉश' (दिखावा) साबित हो रहा है। जनता अब इस खेल को भली-भांति समझ चुकी है कि इस पूरे सिंडिकेट के असली सूत्रधार हृञ्जक्क्र प्रबंधन के वे 'सफेदपोश' अधिकारी हैं, जो एसी कमरों में बैठकर हर महीने करोड़ों का वारा-न्यारा कर रहे हैं।

?2025 का इतिहास गवाह है: सिंडिकेट में सिर्फ नाम बदलते हैं, खेल वही रहता है!

?यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2025 में भी ठीक इसी तरह का दिखावा किया गया था, जब 6 वाहनों को जब्त कर 3 एजेंसियों पर कार्रवाई की बात कहकर मामले को दबा दिया गया था। जनता अब अच्छी तरह जान चुकी है कि कार्रवाई के नाम पर केवल ड्राइवरों को बलि का बकरा बनाया जाता है।

?2025 में भी गाड़ियां पकड़ी गई, 2026 में भी गाड़ियां पकड़ी गई। ?ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के नाम बदलते रहे, लेकिन हृञ्जक्क्र के भीतर बैठा ऐश मैनेजमेंट और सिक्योरिटी विंग का सिंडिकेट जस का तस कायम रहा।अवैध डंपिंग का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका और शहर को जहर परोसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।?हृञ्जक्क्र अफसरों की मिलीभगत के 4 प्रत्यक्ष प्रमाण:?द्बह्लस्स्- पोर्टल को जानबूझकर बायपास करना: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ऑनलाइन द्बह्लस्स्- पोर्टल को बाईपास करके बिना ट्रिप दर्ज किए गाड़ियों को बाहर भेजना बिना हृञ्जक्क्र के आईटी व ऐश अफसरों की सह के संभव ही नहीं है। ?बंद त्रक्कस्- के बावजूद गेट पास जारी होना: वाहन ष्टत्र13, ऋ 6626, ष्टत्र13, ऋ 9418 और ष्टत्र13, ऋ 6625 में त्रक्कस्- बंद या गायब होने के बाद भी संयंत्र के गेट से डिस्पैच क्लियरेंस कैसे मिली? ?फर्जी गंतव्य और फर्जी पावती का खेल: 500 किमी दूर सीमेंट प्लांट में राख खाली होने के फर्जी रिसीविंग कागजात जमा कर करोड़ों रुपये का भाड़ा बिल (स्नह्लद्बद्दद्धह्ल क्चद्बद्यद्य) पास किया जा रहा है।?5 किमी दूर डंपिंग और 1 घंटे में वापसी: गाड़ियां 5 किमी दूर राख फेंककर 1 घंटे में वापस आ रही थीं। हृञ्जक्क्र का टाइम-लॉग सिस्टम सब दर्ज कर रहा था, फिर भी अधिकारी आंखें मूंदे रहे।?पर्यावरण मंत्री के गृह जिले में यह दुस्साहस किसके 'आशीर्वाद' से??सबसे मजे और हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरा फर्जीवाड़ा और पर्यावरण से खिलवाड़ किसी सुदूर क्षेत्र में नहीं, बल्कि स्वयं छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के गृह जिले में धड़ल्ले से चल रहा है!?रायगढ़ की जनता अब खुले तौर पर सवाल पूछ रही है कि आखिर कैबिनेट मंत्री और कड़क छवि वाले विधायक के अपने क्षेत्र में हृञ्जक्क्र के अधिकारी इतना बड़ा घोटाला करने की हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? इसके पीछे केवल दो ही वजहें हो सकती हैं:?या तो शासन-प्रशासन को रायगढ़ की जनता की सेहत और पर्यावरण की कोई परवाह नहीं है...?या फिर इस पूरे एनटीपीसी सिंडिकेट को किसी शक्तिशाली तंत्र का अभय 'आशीर्वाद' प्राप्त है!?2025 बनाम 2026: दिखावे की कार्रवाई की तुलनाकार्रवाई का दिखावा सिंडिकेट की सच्चाई हृञ्जक्क्र अफसरों पर कार्रवाई शून्य2025 में 6 वाहन जब्त, 3 एजेंसियों को नोटिस/ब्लैकलिस्ट का नाटक सिर्फ नाम बदले, अवैध डंपिंग बेधड़क जारी रही हृञ्जक्क्र अधिकारियों पर कार्यवाही शून्य-(जीरो)2026 में 3 वाहन (ष्टत्र13, ऋ 6626, 9418, 6625), ?3.53 लाख पेनल्टीद्बह्लस्स्- पोर्टल बायपास कर रायगढ़ को जहर परोसा गया हृञ्जक्क्र अधिकारियों पर कार्यवाही शून्य- सिर्फ ट्रांसपोर्टर पर गाजअब दिखावा बंद करो, 'सफेदपोश' चेहरों पर चलाओ कार्रवाई का डंडा!

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर होगी 'रन फॉर इंद्रावती' मैराथन

बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने 29 जुलाई को दौड़ेंगे युवा

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को इंद्रावती टाइगर रिजर्व और नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 'रन फॉर इंद्रावती' मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य बाघों, वन्यजीवों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।मैराथन की शुरुआत 29 जुलाई को सुबह 7 बजे इंदिरा स्टेडियम, बीजापुर से होगी। प्रतिभागियों को सुबह 5.30 से 6.30 बजे तक चेस्ट नंबर वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिता 5 और 10 किलोमीटर की दो श्रेणियों में आयोजित होगी, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे।10 किलोमीटर स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 7 हजार, 5 हजार और 4 हजार रुपए के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

वहीं 5 किलोमीटर स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 5 हजार, द्वितीय पुरस्कार 4 हजार और तृतीय पुरस्कार 3 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। इच्छुक प्रतिभागी पोस्टर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। आयोजकों ने जिले सहित प्रदेशभर के युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, वन्यजीव प्रेमियों और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यह मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण के समर्थन में जनजागरूकता का अभियान भी है।

नीट और सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्ष को घेरा

जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने केंद्र सरकार के कदमों का किया समर्थन, विपक्ष पर लगाए राजनीतिक आरोप

बीजापुर/मूक पत्रिका

भाजपा के जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के हालिया कदमों से विपक्ष का रुख उजागर हुआ है।शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नाग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामलों में त्वरित कार्रवाई की दिशा में पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों के खिलाफ कड़े दंड और अन्य सख्त कानूनी प्रावधानों पर काम कर रही है।भाजपा नेता ने दावा किया कि सरकार के सकारात्मक रुख के बाद सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त किया। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और संवाद की पहल का परिणाम बताया।

छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मजदूर नेता ने दी प्रतिक्रिया

विक्रम ठाकुर/कांकेर:-कांकेर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के जिला अध्यक्ष सागर साहू ने इसे छात्रों युवाओं के संघर्ष का जीत बताया है। साहू ने बताया कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग पर एकत्रित हुए छात्रों युवाओं पर पुलुसी बर्बर हमला के बाद भी छात्रों युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर डेट रहे। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से विस्तारित होकर देश के कोने कोने तक फैल गया था।

1200 शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल

तीन माह के ब्रिज कोर्स के बाद होगी शैक्षणिक स्तर की परीक्षा, उसी आधार पर मिलेगा कक्षा में प्रवेश

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले में शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों को दोबारा स्कूलों से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के करीब 1200 बच्चों को आवासीय पोटाकेबिन विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है। अब इन बच्चों के लिए तीन माह का ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा। मिली जानकारी अनुसार, चिन्हित अधिकांश बच्चे स्कूल की सुविधा नहीं होने, घरेलू जिम्मेदारियों या नक्सल प्रभावित परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से दूर हो गए थे। कुछ बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि कई पहली बार विद्यालय से जुड़ रहे हैं।शिक्षा विभाग ने बच्चों को विद्यालयीन वातावरण के अनुरूप तैयार करने के लिए शुरुआती दिनों में खेलकूद, चित्रकला, नृत्य, क्राफ्ट, भ्रमण और अन्य रचनात्मक गतिविधियां कराई। इसके बाद अब उनकी शैक्षणिक क्षमता का आकलन करने के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जा रहा है। कोर्स के दौरान भाषा और गणित की बुनियादी दक्षताओं को विकसित किया जाएगा। तीन माह बाद परीक्षा लेकर बच्चों को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर ब्रिज कोर्स से जुड़े बच्चों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन-अध्यापन और भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।डीईओ राजेश पांडेय ने बताया कि वर्षों बाद बड़ी संख्या में शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चे फिर से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य शैक्षणिक स्तर तक लाने और उनके समग्र विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

डीएमएफसे बदलेगी कांकेर की तस्वीर, 306.50 करोड़ की विकास योजना को मिली हरी झंडी

स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, सड़क, रोजगार, महिला एवं बाल कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में होंगे विकास कार्य, गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगा विशेष फोकस

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ :-कांकेर 25 जुलाई जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 306.50 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने की। बैठक में सांसद भोजराज नाग, विधायक आशाराम नेताम, विधायक विक्रम उसेंडी, विधायक सावित्री मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि स्वीकृत राशि में से 214 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, पेयजल, पशुपालन, कौशल विकास, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा आवास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च किए जाएंगे। वहीं 92.50 करोड़ रुपये सिंचाई, ऊर्जा, जल विभाजक विकास एवं अन्य आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े विकास कार्यों पर व्यय किए जाएंगे। बैठक में बेसलाइन सर्वे एवं गैप एनालिसिस के आधार पर तैयार पंचवर्षीय योजना, वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना तथा अक्षय निधि के लिए 10 प्रतिशत राशि के प्रावधान की जानकारी भी दी गई। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी ने डीएमएफ के उद्देश्यों, भारत सरकार की नई गाइडलाइन तथा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015 के प्रावधानों से अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने, गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध उत्खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए। बैठक में नगर पालिका परिषद कांकेर के अध्यक्ष अरुण कौशिक, डीएफओ रोनक गोयल, शासी परिषद के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ष 2025-26 के खेल पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

डाइट मनी और नगद राशि पुरस्कार हेतु आवेदन सीधे खेल संचालनालय या जिला कार्यालय में जमा होंगे

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों और कोच को खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है एवं राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों (शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, पंकज विक्रम सम्मान, विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि) हेतु आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 05 अगस्त 2026 तक विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य) के उपलब्धियों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।पुरस्कार संबंधी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की वेबसाइट (द्धह्लह्लश्च://ह्यश्चशह्लह्यस्42.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ) पर अपलोड किये गये आवेदन ही मान्य होंगे। केवल नगद राशि पुरस्कार एवं डाइटमनी हेतु आवेदन सीधे संचालनालय, खेल संघ के माध्यम से संचालनालय एवं जिला कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।1. शहीद राजीव पांडे पुरस्कार: इसके अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो।2. शहीद कौशल यादव पुरस्कार: ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया है, जो जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो।3. पंकज विक्रम सम्मान: ऐसे खिलाड़ियों को प्रदाय किया जाता है जिन्होंने विगत 5 वर्षों में 04 बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो।

4. वीर हनुमान सिंह पुरस्कार: प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को प्रदाय किया जाता है।

5. शहीद विनोद चौबे सम्मान: खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो जिसके आधार पर उन्हें सम्मानित करने हेतु विचार किया जाएगा।6. मुख्यमंत्री ट्रॉफी: सीनियर वर्ग या जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदाय की जाती है।7. नगद राशि पुरस्कार: सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब-जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद राशि पुरस्कार प्रदाय किया जाता है।8. डाइट मनी (खेलवृत्ति): सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब-जूनियर वर्ग की राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को डाइट मनी प्रदाय किया जाता है। डाइट मनी (खेलवृत्ति) हेतु खिलाड़ियों की अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरसीवा में साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बरमकेला/मूक पत्रिका

डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसी गति से साइबर अपराधों के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से स्कूली छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यमों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव तथा बाल संरक्षण संबंधी कानूनों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को लेकर आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरसीवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी साइबर सेल श्री राम कुमार मानिकपुरी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर ठग फर्जी वेबसाइट, फिशिंग लिंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी तथा ओटीपी के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी अथवा अन्य गोपनीय जानकारियां साझा न करें। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सोच-समझकर किया जाना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा न करें। साइबर अपराध की किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए अपना संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया।

कार्यक्रम के दौरान जिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती पायल साहू ने बच्चों के अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों, पॉक्सो अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार के बाल शोषण, उत्पीड़न अथवा अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

उन्होंने छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों से संबंधित किसी भी आपात स्थिति या अपराध की सूचना इस हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी समस्या को अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों से साझा करने की सलाह दी।इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से श्रीमती गीता नायक, श्री दीपक देवांगन एवं श्रीमती पुष्पा यादव की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने भी विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री बी.एल. कुर्रे ने सभी अतिथियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और सजग नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों तथा विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू संचालन में सक्रिय सहभागिता निभाई। छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।यह जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल जीवन, सामाजिक जिम्मेदारियों तथा बाल अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

संपादकीय

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की घटना पर नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन क्या इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। सवाल है कि युद्ध के नियमों के विपरीत किसी असैन्य जहाज को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि उस पर झंडा भी किसी तीसरे देश का लगा हुआ था? भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग बेहतर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलती है। मगर सवाल है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूक्रेन के तट से रवाना हो रहे गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हाल ही में हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत की घटना से यह सवाल एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है।इससे पहले होर्मुज जलमार्ग में तेल के एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की घटना पर नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन क्या इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जाहिर है, भारत को ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाना चाहिए और पीड़ित परिवारों को भी हरसंभव सहायता मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।गौरतलब है कि बीती 19 जुलाई की शाम को एमवी गोल्डन लियो नामक वाणिज्यिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हमला हुआ था। उस वक्त जहाज पर चालक दल के सत्रह सदस्य सवार थे, जिनमें चार भारतीयों समेत दस लोगों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि यह हमला रूसी सेना की ओर से किया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला है।मगर सवाल है कि युद्ध के नियमों के विपरीत किसी असैन्य जहाज को निशाना क्यों बनाया गया? जबकि उस पर झंडा भी किसी तीसरे देश का लगा हुआ था। दूसरा, भारत सरकार को इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अपने देश के नागरिकों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध के प्रभाव वाले क्षेत्रों से कैसे दूर रखा जाए। साथ ही इस तरह के हमलों में पीड़ित परिवारों की मदद और मृतकों के शव शीघ्र स्वदेश लाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाना चाहिए।

जंतर-मंतर के मुखौटों के पीछे का सच !

(कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल)

भाजपा और मोदी विरोध के सभी गिरोह एकजुट हुए। भरपूर पैसा बहाया गया। संसद घेरने के लिए भीड़ को उतार दिया गया। जिन क्षेत्रों में ड्रोन प्रतिबंधित थे, वहां शक्ति प्रदर्शन-प्रचार के लिए ड्रोन कैमरे चलाए गए। कश्मीर की तर्ज़ पर भीड़ के ज़रिए पुलिस पर संगठित योजना के तहत पथराव कराया गया। पुलिस वालों और महिला पत्रकारों की लिंचिंग की कोशिशें की गईं। भारत के संविधान ने जिस संसद का गठन किया। जो संसद हमारे देश की सांविधानिक आधारशिला है। उसे उखाड़ फेंकने की बातें दुहराई गईं। भारत को नेपाल बनाने का कॉकरोचों ने दंभ भरा। ये तब हो रहा था जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और चर्चा की।

फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताक़त झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे दंगे फैलाए जाएं। कन्वर्जन कराने वाले गिरोह के वो लोग जो [illegible] की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम [illegible] एजेंसीज हायर की गईं।

चाहे [illegible] हो याकि कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उन्हें कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी दोषी बख़्शे नहीं जाने चाहिए। किसी भी एग्जाम में जालसाज़ी, पेपरलीक जैसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने की संपूर्ण जवाबदेही सरकार की है। कोई व्यक्ति हो, संगठन हों। सबको अपनी-अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहिए। आप इस्तीफा मांगिए। याकि जो भी संविधान सम्मत विरोध के शांतिपूर्ण तरीके हों, उन सबको करिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही भारत है। संवाद के रास्ते हमेशा ही खुले होने चाहिए। सरकार का ये उत्तरदायित्व भी है। भौगोलिक संदर्भ

लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि– देश में अराजकता के संगठित कृत्य को आंदोलन कहकर स्वीकार कर लिया जाएगा। भारत के युवाओं को काकरोच कहकर अपमानित करने वाली इंटरनेशनल साज़िशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत में कॉकरोच शब्द और दिल्ली जंतर-मंतर कनेक्शन अब नए संदर्भ में अपरिचित नहीं रह गया है। सबसे पहले कुछ जमूरों ने अमेरिकी में बैठकर- भारत के युवाओं को- भारत के सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ़त में काकरोच कहा। फिर भाजपा और मोदी विरोध की पटकथा लिखी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने मई 2026 में ये टिप्पणी फर्जी डिग्री के ज़रिए वकालत करने वाले वकीलों पर की थी। इसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन डीप स्टेट ने आम आदमी पार्टी के जमूरों को आगे कर - भारत की न्यायपालिका के खि़लाफ़ उकसाया। यहीं से काकरोच शब्द को भारत के युवाओं के माथे पर चस्पा करने की योजना को मूर्तरूप दिया गया।

आम आदमी पार्टी का जमूरा - दीपके भारत आया, इधर-उधर प्रदर्शन के लिए गया लेकिन धूप तक बर्दाश्त न कर पाया। तत्पश्चात एफसीआरए के विरोध में सोनम वांगचुक को अमेरिकी मूल की उनकी पत्नी –रेबेका नॉर्मन के ज़रिए प्रोटेस्ट का चेहरा बनाकर 'जंतर-मंतर' के मैदान में भूख हड़ताल के लिए उतार दिया गया। जहां इमोशनली-सेंटीमेंट भुनाने के तमाम प्रयोजन रचे जाने लगे। नेपाल और बांग्लादेश जैसे सत्ता की रिजीम चेंज करने का खाका खींचा जाने लगा।

फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताक़त झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे दंगे फैलाए जाएं। कन्वर्जन कराने वाले गिरोह के वो लोग जो [illegible] की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम पीआर एजेंसीज हायर की गईं। सेलीब्रिटीज कहे जाने वाले क़ौमी लोग– हिंदुत्व को समस करने के लिए उतर आए। विदेशी और देशी पैसों से सोशल मीडिया कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया। भावुक युवाओं ने भी देखा-सुनी ऐसी तमाम स्टोरीज सोशल मीडिया में शेयर कीं। जबकि इस तथाकथित आंदोलन में शिक्षाविद्, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कहीं नज़र नहीं आए। अगर स्टूडेंट्स नज़र आए भी तो उन्हें मंच पर कहीं स्थान नहीं मिला। सिर्फ़ कुछ हाईजैकर्स , कॉमेडियन, नेता और भारत विरोधी -हिन्दुत्व विरोधी बातें कहने वाले चेहरे नज़र आए। कंटेंट क्रिएटर्स ही दिखते रहे।

प्रोफेशनल पीआर स्टाइल में प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा हुआ। एआईएसएफ, एसएफआई समेत तमाम गद्दार वामपंथियों का इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ। जेएनयी-एएमयू की तर्ज पर अर्बन नक्सल गिरोह की जिहादी डफली सुनाई देने लगी। एलजीबीटीक्यू का प्रचार-प्रसार किया जाने लगा। हिन्दू घ्रणा का परचम बुलंद किया जाने लगा। लेकिन इन जमूरों में से कोई भूख हड़ताल का साहस न कर पाया जिससे तंग आकर खुद सोनम वांगचुक तक को ये कहना पड़ा कि– आप लोग यहां आकर ठूंस-ठूंस कर खा रहे हैं, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है।

इतना ही नहीं ये जंतर-मंतर वाले कॉकरोच - दिन के बाद रात को एसी रूम में जाकर सोते थे। पार्टियां करने में जुट जाते थे। फिर अपने रुटीन में जुट जाते थे। अंततोगत्वा 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। किन्तु ये कॉकरोच, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से- सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल से प्रायवेट अस्पताल में भर्ती कराने की ज़िद पर अड़े। दिल्ली हाईकोर्ट गए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि- सफदरजंग अस्पताल से कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहां उनकी समुचित देखभाल हो रही है।

20 जुलाई 2026 को बिना परमिशन के संसद मार्च करने का शाहीन बाग-सीएए दंगे वाली स्टाइल में अभियान चलाया गया। कांग्रेस, आप,समाजवादी पार्टी, भीम-मीम के गठजोड़, लेफ्ट पार्टियां, कन्वर्जन कराने वाले एनजीओ अर्बन नक्सली, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज, सो-रोस-डीप स्टेट के वालंटियर्स - सब देश के यूथ के कंधों पर बंदूक रखकर उतर आए। सबने भीड़ जुटाने का पर्याप्त प्रबंध किया।

भाजपा और मोदी विरोध के सभी गिरोह एकजुट हुए। भरपूर पैसा बहाया गया। संसद घेरने के लिए भीड़ को उतार दिया गया। जिन क्षेत्रों में ड्रोन प्रतिबंधित थे, वहां शक्ति प्रदर्शन-प्रचार के लिए ड्रोन कैमरे चलाए गए। कश्मीर की तर्ज़ पर भीड़ के ज़रिए पुलिस पर संगठित योजना के तहत पथराव कराया गया। पुलिस वालों और महिला पत्रकारों की लिंचिंग की कोशिशें की गईं। भारत के संविधान ने जिस संसद का गठन किया। जो संसद हमारे देश की सांविधानिक आधारशिला है। उसे उखाड़ फेंकने की बातें दुहराई गईं। भारत को नेपाल बनाने का कॉकरोचों ने दंभ भरा। ये तब हो रहा था जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और चर्चा की।

आप सोचिए कि- इस संगठित भीड़ ने जो उपद्रव किए क्या ये लोकतांत्रिक कृत्य हैं? क्या ये किसी मांग को मनवाने की बातें हैं? किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन में पत्थरबाजी कहां से होने लगी, अचानक से इतने पत्थर क्या बिना पूर्व तैयारी के आ गए? क्या ये संगठित अराजकता-भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता, प्रगति को रोकने के षड्यंत्र नहीं हैं? ये षड्यंत्र उस युवा के सेंटीमेंट्स के ज़रिए लॉन्च किए जा रहे हैं। जो भारत की प्रगति का आधार है। मैं भी युवा हूं और तथाकथित [illegible] की परिभाषा में भी आता हूं। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। स्वातंत्र्य क्रांति के क्रांतिवीर हैं। भगवान राम और कृष्ण हैं। सरकार से हम सबकी अपेक्षाएं हैं। अपनी मांगों और विरोध के हमारे पास सांविधानिक तौर तरीके हैं। अपनी पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मुझे भारत की स्थिरता के ख़िलाफ़ बरगला लेगा। क्या कोई भी टूल बनाकर हमें किसी आग में झोंक देगा और हम उसमें कूद पड़ेंगे? ये हम युवाओं को सोचना और समझना चाहिए।

जंतर-मंतर में सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाकर जिस शातिराना ढंग से भारत घ्रणा-हिन्दू घ्रणा का प्रहसन किया गया।उसे इस देश का युवा अच्छी तरह से जानता है। युवा साथियों को इसे और बारीकी से समझना चाहिए। ताकि हम किसी टूलकिट का शिकार न बनें। जंतर-मंतर में जिस तरह से भगवान राम को अपमानित किया गया। भारत की संस्कृति के ख़िलाफ़ ज़हर उगला गया। ब्राह्मणों, हिन्दुत्व को ख़त्म करने का ऐलान किया जाता रहा। आरएसएस के खिलाफ़ नारेबाजी की जाती रही। भारतीयता की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 को ख़त्म करने की जिहादी पोस्टर बनाए गए।नारेबाज़ी की गई। काफ़िरों के कत्लेआम के लिए फ़ैज़ की बस नाम रहेगा अल्लाह का जैसा जिहादी ऐलान किया गया। यानी भारत के इस्लामीकरण का फतवा जारी किया गया।

क्या ये सब किसी भी हिसाब से जायज़ कहा जाएगा? क्या ये किसी न्याय की लड़ाई थी? पूरे प्रहसन के दौरान जिस तरीक़े से हर दिन भारत द्वेष का विष वमन किया जाता रहा। संविधान और तिरंगे की ओट में छिपकर– भारत के संविधान को चुनौती दी जाती रही। भारत की न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा किया जाता रहा। संसद को उखाड़ फेंकने के नारे गढ़े गए। भारत को –हिंसा, दंगों की आग में झोंकने के लिए – नेपाल बनाने के जो संदेश दिए गए। वो गंभीर हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती भी हैं। ये कोरी भावुकता तो कतई नहीं हो सकती। ये निश्चित ही भारत की शक्ति, सामर्थ्य के खिलाफ़ एक सुनियोजित साज़िश है। इसमें सत्ता की भूखी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता भी अव्वल हैं। जो बांग्लादेश और नेपाल हिंसा के बाद वहां हुए तख्तापलट के समय से ही - भारत के युवाओं को हिंसा, उपद्रव के लिए उकसा रहे हैं। कभी वो जेन जेड के नाम पर उकसाते हैं।

दुनिया किसी चाहने वाले की शर्त से नहीं चलती, सब परस्पर निर्भरता से जीते

(क्षमा शर्मा)

किसी डाक्टर से जब इलाज कराने जाते हैं, तब वह बीमारी देखकर दवाएं देगा। ये दवाएं वे होंगी, जो हमारे लिए जरूरी हैं, न कि वे जिन्हें हम खाना चाहते हैं।अक्सर लेखों, भाषणों और किताबों में एक बात पढ़ने को मिलती है कि हमें अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहिए। ये शर्तें क्या हैं, क्यों हैं, कैसी हैं, किसलिए हैं, कोई नहीं बताता। अगर इसे जीवन के तमाम पक्षों पर घटित किया जाए, तो पता चलता है कि ऐसी बातें सिर्फ मन मोदक की तरह ही हैं। जैसे कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, उसे किसी और ने लिखा है। किसी ने छापा है।

लेखक ने अपनी पसंद की किताब लिखी है, या हो सकता है प्रकाशक ने लिखवाई हो। किसी वाणिज्यिक वेबसाइट या किसी दुकान से खरीदी गई है। यह ठीक है कि इसे पाठक की रुचियों के हिसाब से ही तैयार किया गया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को पसंद आए। यानी कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं, तो रुचि, अरुचि तो हो सकती है, लेकिन शायद वे शर्तें इस पर लागू न हों, जो हमारी हों।

इसी तरह जब कोई कहीं भाषण देने गया है, तो उसे किसी और ने बुलाया होता है। मंच किसी संस्थान का है, माइक किसी और का। कुर्सियों और पानी का इंतजाम भी। भाषण देने वालों में जो लोग होंगे, वे भी वही नहीं बोलेंगे, जो हम चाहते हैं। बोलने का समय कितना है, इसे किसी और ने ही तय किया होता है। बोलने का विषय भी बताया गया है। ऐसे में जो बोलने वाला है, उस पर पहले से ही बहुत कुछ थोपा गया है।

अब कोई यह मान ले कि वह विषय से बाहर जाकर बोलेगा, जितने समय चाहे बोलेगा, मंच से नीचे आकर बोलेगा, तो क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। अगर कोई लेखक एक लेख लिख रहा है, तो अखबार या पत्रिका को क्या चाहिए, यह पहले से ही पता होगा। लेख कितने शब्दों का होगा, यह जानकारी भी अवश्य होगी। हालांकि कई बार लोग निर्धारित शब्दों से काफी कम या फिर काफी ज्यादा बड़ा लेख भेज देते हैं।

इसके अलावा, लेख में क्या हो, इसके मुकाबले क्या नहीं होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए। मगर वह कब छपेगा, इसे कोई और ही तय करेगा। फिर जिस कागज पर छपेगा, वह कहीं और से आया होगा। छापने के लिए जो स्याही इस्तेमाल हुई होगी, वह भी किसी कंपनी की होगी। अखबार पाठक तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों के हाथों से गुजरा होगा। यानी कि वे शर्तें उसकी नहीं होंगी, जिसने एक लेख लिखा है।

इसी तरह किसान अपने खेत में क्या बोए, यह मौसम और बाजार की जरूरत के हिसाब से ही तय होगा। यह नहीं कि किसान की मर्जी क्या है, इस बात से फसल उगेगी। फिर खेत में पानी या तो बारिश से आएगा या ट्यूबवेल से। फसल की गुड़ाई, निराई, कटाई, बाजार तक पहुंचने में बहुत-सी मशीनों और मानवीय श्रम की जरूरत होगी।

इसी तरह किसी डाक्टर से जब इलाज कराने जाते हैं, तब वह बीमारी देखकर दवाएं देगा। ये दवाएं वे होंगी, जो हमारे लिए जरूरी हैं, न कि वे जिन्हें हम खाना चाहते हैं। हां, किसी दवा से एलर्जी है, तो वह अलग बात है। न ही ऐसा चल सकता है कि मनमाफिक दवा मिल सके।

दूर क्यों जाया जाए, अगर हम किसी सड़क पर चल रहे हैं तो दाएं, बाएं देखकर चलना पड़ता है। कौन-सी बस, मेट्रो, कैब, ट्रेन, जहाज अपने निर्धारित समय पर आएगा, अगर यह पता न हो, तो कहीं समय से नहीं पहुंच सकते। इनका आना-जाना हमारी अपनी जरूरत के अनुसार नहीं होता है। हमें इनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम कार चला रहे हैं, तो न केवल दाएं और बाएं, बल्कि पीछे भी देखना पड़ता है।

कार की रफ्तार भी सड़क की भीड़-भाड़ को देखते हुए ही तय होती है। कार की सर्विसिंग कहीं करानी पड़ती है, तो पेट्रोल कहीं और से लेना पड़ता है। टूट-फूट हो, तो मैकेनिक से ठीक कराना पड़ता है। गाड़ी चाहे जितनी पसंद हो, उसमें एक निशान भी न लगा हो, इंजन भी ठीक से काम करता हो, तब भी अगर डीजल से चलने वाली गाड़ी दस साल और पेट्रोल वाली पंद्रह साल पुरानी हो गई, तो उसे हटाना पड़ता है।

हालांकि अमेरिका या यूरोप मे पंद्रह साल का ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां जब तक गाड़ी ठीक है, चलाई जा सकती है। सिर्फ प्रदूषण का ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी होने पर उसे दुरुस्त करने वाला पुर्जा बदलवा लिया जाता है। मगर अपने यहां प्रदूषण हटाने और आटोमोबाइल उद्योग को लाभ दिलाने के लिए ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, जिससे कि यह उद्योग चलता, चमकता रहे।

इस नियम से प्रदूषण भी कितना हटा है, सब जानते हैं। ऐसे वक्त में भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहता है, जब प्रदूषण फैलाने वाले कारक अपने निचले स्तर पर रहते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर यह जीवन है, तो प्रति पल हमें दूसरों के साथ मिलकर जीना पड़ता है।

पर्यटकों की भीड़ से कराह रहे पहाड़, क्या हिमालय अपनी सीमा तक पहुंच चुका है?

(चंद्रशेखर तिवारी)

पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं। अनेक गांवों में घरों में पर्यटकों को ठहराने (होमस्टे) की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई परिवार, जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है।

वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। निस्संदेह इससे राजस्व संसाधनों के नए द्वार खुले हैं, लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। हिमालय केवल एक पर्वत-श्रृंखला नहीं है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की जल, जंगल, जैव-विविधता, संस्कृति और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अपनी भौगोलिक विशिष्टता, लोक-सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक आभा के कारण हिमालय सदियों से मानव समाज को आकर्षित करता रहा है। इसकी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, कल-कल बहती नदियां, घने वन, प्राचीन तीर्थ स्थल और लोक-स्मृतियां इसे विश्व की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। यही कारण है कि साधकों, श्रद्धालुओं, पर्वतारोहियों और प्रकृति-प्रेमियों का हिमालय के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा है। मगर, वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। निस्संदेह इससे राजस्व संसाधनों के नए द्वार खुले हैं, लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का बेतहाशा विस्तार हुआ है। पर्यटन को अब विकास के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से पर्यटन के प्रचार से इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और मणिकर्ण के अलावा शिमला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली, रोहतांग दर्रा, स्पीति घाटी और पार्वती घाटी जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और चारधाम यात्रा के अलावा औली, मसूरी, बुग्याल, हरकीदून, रूपकुंड, नैनीताल, सुंदरढूंगा, छोटा कैलाश तथा पिंडारी जैसे स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। पर्यटन के ये ज्यादातर केंद्र अब केवल मौसमी गंतव्य नहीं रहे, बल्कि वर्ष भर व्यस्त रहने वाले आर्थिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में वर्ष 2025 में करीब सवा तीन करोड़ पर्यटक पहुंचे। इसी तरह उत्तराखंड में वर्ष 2025 में रिकॉर्डतोड़ पर्यटक पहुंचे। इस दौरान यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या छह करोड़ से अधिक रही, जिनमें 1.92 करोड़ विदेशी पर्यटक थे। इसमें सबसे अधिक पर्यटक हरिद्वार, देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में आए। पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं। अनेक गांवों में घरों में पर्यटकों को ठहराने (होमस्टे) की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई परिवार, जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है। मगर इस उत्साहजनक परिदृश्य के बीच एक मूलभूत प्रश्न लगातार उभरता जा

रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र विकास की वर्तमान गति और स्वरूप को वहन करने की क्षमता रखता है? यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत-श्रृंखलाओं में से एक है और यहां की ढलानें अपेक्षाकृत अस्थिर तथा जलस्रोत सीमित हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जो ढांचागत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहां बार-बार होने वाले भूस्खलन और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न संकट हमें यह याद दिलाता है कि यदि पर्यटन विकास की प्रक्रिया में स्थानीय पारिस्थितिकी की अनदेखी की जाती है, तो उसका परिणाम दीर्घकालिक संकट के रूप में सामने आ सकता है। देश में पर्यटन विकास का मूल्यांकन प्रायः पर्यटकों की संख्या, होटल के कमरों की संख्या में वृद्धि, सड़क निर्माण और निवेश की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यह पैमाना मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीमा तक उपयुक्त हो सकता है, मगर हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में वास्तविक प्रश्न यह होना चाहिए कि पर्यटन स्थानीय समाज, संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों को कितना सशक्त बना रहा है। यदि किसी क्षेत्र में पर्यटन के कारण जलस्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा हो, कचरे का संकट उत्पन्न हो रहा हो, स्थानीय स्थापत्य नष्ट हो रहा हो और सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ रही हो, तो उस विकास की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक पर्यटन स्थलों पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहाड़ों की सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है और निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का पारंपरिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से जल, भूमि और ऊर्जा संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते दबाव से यातायात अव्यवस्था और कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति संकेत देती है कि पर्यटन विकास की वर्तमान दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास की अवधारणा अक्सर मैदानी मॉडल से प्रभावित दिखाई देती है। चौड़ी सड़कों, विशाल भवनों और बड़े होटल परिसरों को प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और पारिस्थितिक सीमाएं भिन्न हैं।

डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता में वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता में विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य से वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं पास्को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा एवं जागरूकता का उत्कृष्ट परिचय दिया। वाद-विवाद प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ÷प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध÷ विषय निर्धारित किया गया, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने ÷कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.)के लाभ एवं हानि÷ विषय पर प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने पक्ष एवं विपक्ष में तार्किक तर्क रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, आत्मविश्वास तथा विषय की गहन समझ का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता एवं तार्किक चिंतन का विकास हुआ। इसके पश्चात विद्यालय में पॉस्को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग समूहों में बैठाकर उनकी आयु के अनुरूप पॉस्को अधिनियम, व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छे एवं बुरे स्पर्श (गुड़ टच व बेड टच), साइबर सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की जानकारी तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति सदैव सजग एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य पी एल जायसवाल ने जानकारी में बताया कि वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास एवं प्रभावी अभिव्यक्ति का विकास करती हैं, वहीं पॉस्को जागरूकता कार्यक्रम बच्चों को सुरक्षित, सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ललित देवांगन, अकलेश पटेल, अनिल चंद्रवंशी, गोविन्द साहू, अजय सेन, आयुषी जैन, विमल साहू, राजा तंतुवाय, अभिषेक दुबे, संदीप कुमार, रेणुका पटेल, साक्षी शर्मा, ऐश्वर्य देशमुख, ममता चंद्राकर, गायत्री सिन्हा, वर्षा वैष्णव, शोभारानी साहू, अनिल कुमार, प्रकाश भोई, प्रीति यादव, प्रांजलि ठाकुर, आर्या निधि, लेखनी चंद्राकर, भुनेश्वरी चंद्राकर, नीलमणि, यामिनी साहू, भारती भट्ट, कैलाश सिंह, भारती बंजारे, रुद्राभिषेक सोनी, कुसुम साहू, सुखदेव साहू, रूखमणी चंद्राकर, रामेश्वरी चंद्राकर, युवराज चंद्राकर, नरेश साहू, विजय चंद्राकर, कुंती यादव आदि सभी ने विद्यालय के कार्यक्रम के सराहना किए।

रायगढ़-लैलूंगा मार्ग पर एबीवीपी का हल्लाबोल: शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर डटे सैकड़ों छात्र और कार्यकर्ता

लैलूंगा/मूक पत्रिका

क्षेत्र में बढ़ती जनसमस्याओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रही शराब दुकान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ॠक्क) का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लैलूंगा में एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार हुंकार भरते हुए व्यस्ततम रायगढ़-लैलूंगा मुख्य मार्ग पर जोरदार चक्काजाम कर दिया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग मुख्य मार्ग के पास स्थित शराब भट्टी (देशी/विदेशी शराब दुकान) को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने की है।

?मुख्य मार्ग पर शराब दुकान होने से बढ़ रहे हादसे और असामाजिक गतिविधियां-?प्रदर्शकारियों का कहना है कि लैलूंगा और रायगढ़ को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग पर शराब दुकान संचालित होने के कारण दिनभर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मार्ग से स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं, महिलाएं और आम नागरिक रोजाना गुजरते हैं, जिससे छेड़खानी, फब्तियां कसने और आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। शराब प्रेमियों द्वारा सड़क किनारे वाहन खड़े करने से आवागमन भी बाधित होता है, जिससे क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है।

प्रशासन को दी चेतावनी–हटाएं वरना होगा उग्र आंदोलन-?प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई बार ज्ञापन सौंपने और मौखिक एवं लिखित शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

?आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने 1 महीने के भीतर इस शराब भट्टी को मुख्य मार्ग से नहीं हटाया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और क्षेत्रवासी इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

रुद्र सेना जिला बेमेतरा की प्रथम संगठनात्मक सूची जारी, संगठन विस्तार को मिलेगी नई गति

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रुद्र सेना जिला बेमेतरा की प्रथम संगठनात्मक सूची जारी कर संगठन को मजबूत एवं जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह नियुक्तियां धर्म स्तंभ काउंसिल के प्रमुख संरक्षक, दक्षिण कौशल पीठ के महंत परम पूज्य गुरुदेव राजीव लोचन दास जी महाराज एवं राम जानकी मंदिर के महंत पूज्य सुरेंद्र दास जी महाराज के पावन आशीर्वाद तथा रुद्र सेना प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे के निर्देशानुसार की गई हैं। संगठनात्मक प्रक्रिया धर्म स्तंभ काउंसिल के वरिष्ठ सलाहकार सौरभ निर्वाणी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।जिलाध्यक्ष आशीष जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन की मजबूती एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। जारी सूची के अनुसार धनी राम निर्मलकर एवं रोशन धर दीवान को उपाध्यक्ष, अंकुश तिवारी को महामंत्री (संगठन) एवं सोशल मीडिया प्रभारी, शुभम दुबे को महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी, अजय देवांगन, अजय सिन्हा, विकास ठाकुर तथा संजय साहू को मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं कोदू राम साहू को नवागढ़ विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आशीष जैन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन के सभी सदस्य सनातन संस्कृति, गौ संरक्षण, धर्म जागरण एवं सामाजिक समरसता के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि नवगठित टीम संगठन की विचारधारा को मजबूत करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य करेगी। साथ ही रुद्र सेना धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

आखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 28 जुलाई को

गुजरात में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू और पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर देश के पत्रकार एकत्रित होंगे।

छत्तीसगढ़ से भी पत्रकारों की टीम आयोजन में शामिल होने हेतू गुजरात के गांधीनगर के लिए रवाना

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

गांधीनगर-सरखेज हाईवे पर स्थित जासपुर में, वैष्णोदेवी मंदिर के सामने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति गुजरात के द्वारा एक भव्य 'गुजरात राष्ट्रीय अधिवेशन' का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम में पूरे गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के अलावा देश के कई राज्यों के बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु एकत्रित होंगे। यह महाधिवेशन राज्य में मीडिया बिरादरी की एकजुटता और संगठन की ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेगा।और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को रखेगा।

पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा अधिवेशन विशेष रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र और पत्रकारों के अधिकारों को समर्पित है। वर्तमान समय में निष्पक्ष,निर्भीक और पारदर्शी पत्रकारिता के सामने आने वाली दैनिक चुनौतियों तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की समस्याओं पर इस अधिवेशन में व्यापक रूप से वैचारिक मंथन किया जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह मंच एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अध्यक्ष एवं अन्य पत्रकार हुए रवाना... उक्त कार्यक्रम को लेकर पूरे देशभर के पत्रकारों में खासा उत्साह और जागरूकता बढ़ रही है और इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से भी जिलाध्यक्ष सहित अन्य पत्रकार साथी आज तड़के सुबह लगभग 03 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने हेतू विशेष रूप से प्रस्थान किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई पटेल का कहना..... उपरोक्त संबंध में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इस राष्ट्रीय स्तरीय महाधिवेशन का मुख्य आकर्षण 'पत्रकार सुरक्षा कानून' की आवश्यकता और उसके त्वरित क्रियान्वयन पर होने वाली गहन चर्चा होगी। पूरे राज्य से आए पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और समिति के पदाधिकारी एक मंच पर आकर इस कानून के विभिन्न पहलुओं और इसे जल्द से जल्द लागू करवाने की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करेंगे, ताकि पत्रकारों के लिए एक निडर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित यह अधिवेशन देश के सभी पत्रकारों को एक सूत्र में बांधने और उनके हकों की आवाज को सरकार व समाज तक मजबूती से पहुंचाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। आयोजन समिति पूरे गुजरात के साथ देश के सभी मीडियाकर्मियों से इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने और इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान करती है।

सिंघौरी स्कूल में एक पेड़ मां के नाम 3.0 के तहत किया गया पौधरोपण

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल सिंघौरी में बस्तामुक्त दिवस पर वृक्षारोपण किया गया।यह कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत आयोजन किया गया।संस्था प्रमुख सरस्वती साहू ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनो को साकार करने के लिए किया जा रहा है।जिसका मुख्य उद्देश्य मिशन ल्लक्ष्श्र और इको क्लब के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। शाला परिसर में शिक्षक एंव बच्चों द्वारा मिलकर कदम,आंवला,गुड़हल,शहतूत के साथ साथ रंग बिरंगी फूलों का भी पौधा लगाये गये।इस अवसर पर देवेंद्र साहू,नुतेश्वर चंद्राकर, प्रशांत बघेल,शशिकला यादव,किरण खरे, धनी राम बंजारे (संकुल समन्वयक),पूनम साहू एंव साजन वर्मा उपस्थित रहे।

एमएसपी प्लांट में 14 लाख कीमती 30 टन लोहा हेराफेरी का खुलासा फर्जी ड्राइवर, बदला हुआ नंबर प्लेट और सुनियोजित साजिश का च्रधरनगर पुलिस ने किया पर्दाफाश

रायगढ़ /मूक पत्रिका

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे ÷ऑपरेशन क्लीन हंट÷ के तहत चक्रधरनगर पुलिस ने एमएसपी प्लांट से करीब ?14.22 लाख मूल्य के एमएस चैनल एवं एमएस बीम की सुनियोजित हेराफेरी का पर्दाफाश करते हुए मुख्य साजिशकर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी ड्राइवर, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे ट्रांसपोर्टर के वाहन नंबर का इस्तेमाल कर माल को गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय बेचने की साजिश रची थी। गिरफ्तार आरोपियों को 24 जुलाई 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।प्रकरण में 25 नवंबर 2025 को ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ईश्वरी सिंह ने थाना चक्रधरनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि एमएसपी प्लांट जामगांव से जमशेदपुर भेजे जाने वाले ?14,22,783 मूल्य के एमएस चैनल एवं एमएस बीम को विनोद साहू नाम बताने वाले एक व्यक्ति ने वाहन क्रमांक छ्व-15ड्ढ्र-2383 के नंबर प्लेट का उपयोग कर लोड कराया, लेकिन माल निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचाया। जांच में पता चला कि आरोपी न तो वास्तविक ड्राइवर था और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस एवं पहचान सही थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, सामान ट्रांसपोटींग के लिए अक्सर वाहन मालिक राजेन्द राम यादव से वाहन लेता है । इसी सिलसिले में दिनांक 19.11.2025 को ड्राईवर विनोद साहू जो स्वयं को ट्रांसपोटर राजेन्द्र राम यादव का ड्राईवर बताते हुए सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम के लिए पूछा जिसे एमएसपी प्लांट जामगांव से जमशेदपुर कुछ सामान भेजना है, बताया था । शिकायत पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 528/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।विवेचना के दौरान पुलिस ने एमएसपी प्लांट के रिकॉर्ड, लोडिंग दस्तावेज, ट्रांसपोर्टर एवं वाहन मालिक से जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि पूरी वारदात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दी गई थी।आरोपित कथित ड्राईवर विनोद साहू ने पत्थलगांव निवासी भगतपुरी गोस्वामी के साथ मिलकर रूक्क कंपनी आया था और ट्रांसपोटर राजेन्द्र राम यादव की गाड़ी बताकर एमएसपी जामगांव रायगढ़ से सिद्ध विनायक स्टील टाटा आदित्यपुर जमशेदपुर के लिए माल लोड कराया गया था किन्तु लोडिंग सामान ड्रायवर सहित गायब हो गया । जब वाहन मालिक राजेन्द्र राम यादव से पूछा तो उसने ड्रायवर विनोद साहू नाम के किसी भी व्यक्ति को जानने से इंकार किया । पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं लगातार पूछताछ के आधार पर भगतपुरी गोस्वामी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी भगतपुरी गोस्वामी निवासी पत्थलगांव ने खुलासा किया कि उसने फर्जी नाम से काम करने वाले ड्राइवर पुष पुरी गोस्वामी (फर्जी नाम विनोद साहू), वाहन मालिक विकास मल्लिक, अपने दोस्त तसौवर अंसारी उर्फ शाहरूख, अभय रवानी एवं प्रेम रवानी के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। आरोपियों ने ट्रांसपोर्टर के वाहन का नंबर प्लेट लगाकर एमएसपी प्लांट से माल लोड कराया और उसे गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय अन्यत्र बेच दिया।पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी भगतपुरी गोस्वामी ने घटना में प्रयुक्त ट्रक सहित लगभग 30 टन एमएस चैनल एवं एमएस बीम का सौदा आरोपी अभय रवानी से लगभग ?7 लाख में किया था। अभय रवानी ने पुलिस को बताया कि उसने माल एवं ट्रक अपने परिचित राजीव मल्लिक निवासी धनबाद को बेच दिया। मामले में पुलिस राजीव मल्लिक तथा फर्जी ड्राइवर पुष पुरी गोस्वामी की तलाश कर रही है प्रकरण में आरोपियों द्वारा साक्ष्य मिटाने एवं योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक अपराध करना पाए जाने पर धारा 338 बीएनएस तथा धारा 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई है। मामले में गिरफ्तार आरोपी भगतपुरी गोस्वामी, तसौवर अंसारी उर्फ शाहरूख, अभय कुमार रवानी एवं प्रेम कुमार रवानी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सराहनीय भूमिका :इस महत्वपूर्ण एवं जटिल आर्थिक अपराध के खुलासे में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा, एएसआई आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक बालचंद राव, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी एवं आरक्षक विक्रम सिंह की विशेष भूमिका रही। चक्रधरनगर पुलिस की सूक्ष्म विवेचना, तकनीकी जांच और साक्ष्यों के विश्लेषण से लंबे समय से लंबित इस धोखाधड़ी का सफल खुलासा संभव हो सका।गिरफ्तार आरोपी-1. भगतपुरी गोस्वामी पिता धरमपुरी उम्र 48 वर्ष निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर (छ0ग0)2. तसौवर अंसारी उर्फ शाहरूख पिता मुख्तार अंसारी उम्र 30 वर्ष निवासी अर्स थाना सेन्हा जिला लोहरदगा (झारखण्ड)।

चक भ्रमण प्रशिक्षण के माध्यम से नदी संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की दी गई जानकारी

हॉफ नदी पुनरुद्धार अभियान को मिला जनसहभागिता का मजबूत आधार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा विकसित भारत जन अभियान के अंतर्गत संचालित हॉफ नदी पुनरुद्धार अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से प्रभावी बनाने की दिशा में शनिवार को जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत अंधियारखोर में ÷चक भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम÷ का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रदान संस्था के तकनीकी सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें नदी पुनरुद्धार, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हॉफ नदी के पुनर्जीवन के लिए ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों, मैदानी अमले एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, नदी तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करना तथा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हॉफ नदी का पुनरुद्धार केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनसहयोग और सामुदायिक सहभागिता से संचालित एक जनआंदोलन है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जन अभियान का स्वरूप देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक ग्राम अपने स्थानीय जल स्रोतों एवं नदी तंत्र के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान रायपुर से आए प्रदान संस्था के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को चक भ्रमण की अवधारणा, उसके उद्देश्य एवं व्यवहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में नदी एवं जल स्रोतों का मानचित्रण, जलग्रहण क्षेत्र का अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, भूमि उपयोग की स्थिति, वनस्पति, जल प्रवाह, मिट्टी की गुणवत्ता तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं व्यवहारिक तरीके से समझाया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रतिभागियों ने हॉफ नदी के तट पर व्यावहारिक चक भ्रमण किया। इस दौरान नदी के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन कर जल प्रवाह, कटाव, अवरोध, भू-आकृति, वनस्पति एवं स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्रकार के मैदानी अध्ययन से नदी पुनरुद्धार की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। नदी किनारे पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण, भू-जल संवर्धन तथा जलवायु संतुलन का संदेश दिया गया। उपस्थित सभी लोगों ने पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हॉफ नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याएँ, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए अपने-अपने ग्रामों में जल संरक्षण एवं नदी पुनरुद्धार गतिविधियों को जनसहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन ÷नदी बचेगी ङ्क प्रकृति सजेगी, जल समृद्धि ङ्क जीवन समृद्धि÷ के प्रेरक संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे अपने गांवों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण एवं नदी संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित कर हॉफ नदी पुनरुद्धार अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करें।

संक्षिप्त समाचार

प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग 5 अगस्त तक

बिलासपुर। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की काउंसलिंग 5 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विभागीय वेबसाइट httpsÑ//eklavya.cg.nic.in/ पर काउंसलिंग हेतु पात्र छात्र-छात्राओं की सूची एवं तिथियां प्रदर्शित कर दी गई हैं। काउंसलिंग चयनित विद्यार्थियों को आवंटित प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनमें कक्षा 8वीं की प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अंकसूची, अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), अल्पसंख्यक वर्ग संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ी जनजाति प्रमाण पत्र तथा विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हैं। काउंसलिंग के बाद प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थियों को तीन दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी से काउंटर हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र संबंधित प्रयास आवासीय विद्यालय में जमा करना होगा।

बिलासपुर में किन्नर की हत्या से सनसनीः मारपीट के बाद गला दबा कर हत्या, सड़क किनारे मिला शव

बिलासपुर। जिले के सकरी थाना क्षेत्र के जोंकी गांव में एक किन्नर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान तनु खान किन्नर के रूप में हुई है। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तनु खान के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया, जहां लोगों की नजर पड़ने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में शुरुआती तौर पर हत्या का संदेह मृतक के कुछ साथी किन्नरों पर जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या की असली वजह और इसमें शामिल आरोपियों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित एंगल पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद हत्या के कारणों और आरोपियों के संबंध में विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़, 6 हुक्का पॉट समेत भारी मात्रा में सामान जब्त

बिलासपुर। शहर के व्यापार विहार इलाके में सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 हुक्का पॉट, 10 हुक्का पाइप और हुक्का फ्लेवर समेत बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान हुक्का बार संचालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि व्यापार विहार में सेंट जेवियर्स स्कूल के पास एक मकान की तीसरी मंजिल पर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की। पुलिस के पहुंचते ही हुक्का पी रहे ग्राहक इधर-उधर भाग गए। वहीं, मौके पर मौजूद हुक्का बार संचालक श्रीकांत प्रजापति, निवासी कुम्हारपारा जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन और सोनू दास मानिकपुरी, निवासी फंदवानी, जिला मुंगेली, पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 6 नग कांच के हुक्का पॉट, 10 हुक्का पाइप, जेल फ्लेवर के 3 पैकेट, 2 नग स्मोकिंग सिरना, 10 हुक्का टिप्स और 1 स्टील की चिमटी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सिगरेट और तंबाकू युक्त फ्लेवर का इस्तेमाल कर ग्राहकों को प्रति घंटे के हिसाब से रुपये लेकर हुक्का पिलाते थे और इससे अवैध आर्थिक लाभ कमा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है।

चंडी आश्रम नेवनारा में त्रिदिवसीय आवासीय संगीत एवं व्याख्यान कार्यशाला का शुभारंभ

मानस साधना, सनातन संस्कृति और लोकजागरण का अभिनव संगम

बेमेतरा/मूक पत्रिका

माँ भद्रकाली जिला मानस संघ, बेमेतरा की अभिनव पहल एवं जय गंगा माँ कार्यसमिति, नेवनारा तथा श्री चंडी आश्रम ट्रस्ट समिति के विशेष सहयोग से आयोजित त्रिदिवसीय आवासीय संगीत एवं व्याख्यान कार्यशाला का शुभारंभ चंडी आश्रम, नेवनारा में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य मौनी महाराज के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वैदिक मंगलाचार, श्रीराम नाम संकीर्तन एवं आध्यात्मिक वातावरण ने सम्पूर्ण परिसर को भक्तिमय बना दिया।

इस अवसर पर माँ भद्रकाली जिला मानस संघ, बेमेतरा के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेमेतरा जिले में इस प्रकार की आवासीय संगीत एवं व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। यह कार्यशाला केवल संगीत अथवा व्याख्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीरामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों, सनातन संस्कृति के आदर्शों, धार्मिक कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों एवं भारतीय जीवन-दर्शन के व्यापक प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन समाज में संस्कार, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का नया प्रकाश फैलाएगा।

कार्यशाला में बेमेतरा सहित विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों प्रतिभागी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर रहे हैं। प्रशिक्षार्थियों को श्रीरामचरितमानस के भाव, गायन शैली, व्याख्यान कला, मंच संचालन, उच्चारण की शुद्धता तथा आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों की बारीकियों का विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कार्यक्रम में जय गंगा माँ कार्यसमिति के अध्यक्ष शालिक राम साहू, स्थानीय सरपंच लोकेश साहू, उपाध्यक्ष माखन साहू, बेमेतरा अध्यक्ष बिहारी लाल यदु, नवागढ़ अध्यक्ष महेशकुमार साहू, छगन साहू, विनय ताम्रकार, टिकेंद्र धीवर, संरक्षक राजकुमार साहू, शिव साहू, विष्णु साहू, संजय वर्मा, राजकुमार निषाद, अलख पाटिल, डॉ. ओंकार चंद्राकर, कल्याणी सेन, पप्पू सेन, नरेंद्र जायसवाल, लता निषाद, गजेन्द्र वर्मा ठेकेलाल देवांगन, ईश्वर सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, मानस साधक, रामायण प्रेमी एवं धर्मानुरागी श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का वातावरण भक्ति, अनुशासन, सेवा और समर्पण की अनुपम भावना से ओत-प्रोत रहा। आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यशाला भविष्य में जिले में मानस अध्ययन, संगीत साधना एवं सनातन संस्कृति के संवर्धन की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

बिलासपुर मंडल में प्रथम हेल्थ केयर कमेटी की बैठक संपन्न

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित हेल्थ केयर कमेटी की प्रथम बैठक अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री जे. एस. मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ शेख सिराजुद्दीन, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्रीमती पूनम चौधरी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ अंशुमान मिश्रा, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री अरविंद विश्वकर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन के समन्वयक श्री विजय अग्निहोत्री तथा समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर, जागरूकता अभियान एवं विशेष चिकित्सा शिविरों के आयोजन की जानकारी दी। इसके पश्चात रेलवे अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों की नियमित आपूर्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा कर्मचारी हित से जुड़े विभिन्न सुझावों की समीक्षा की गई। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री जे. एस. मीना ने अधिकारियों को कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा संबंधी शिकायतों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सभी उपस्थित अधिकारियों ने हेल्थ केयर सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं कर्मचारी हितैषी बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

हसौद थाना परिसर में आरक्षक ने लगाया फाँसी, कारण अज्ञात।

थाना के बैरक में जय लहरे आरक्षक ने लगाया फाँसी।

सक्ती/हसौद/मूक पत्रिका

सक्ती जिले के हसौद थाने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के ऊपर गहरा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। हसौद थाना परिसर भवन में आरक्षक ने फासी लगाया लिया है। आरक्षक के फासी की खबर सुनते ही क्षेत्र सहित जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया व आरक्षण की अज्ञात कारणों से हुई मौत का मामले को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। थाना परिसर में तैनात आरक्षक का फाँसी लगा लेना क्षेत्र के लोगों के समझा से परे है। अब ऐसे में सब से बड़ा सवाल ये है की आम नागरिक के सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। हसौद थाना परिसर में तैनात पुलिसकर्मी का फासी लगा लेना और थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को भनक तक न लगना स्थानीय पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों अधिकारी के कार्यप्रणाली को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम जय लहरे बताया गया रहने वाले भलवाही लगरा पामगढ़ थाना उम्र 41 वर्ष पत्नी श्रीमति दिलेश्वरी लहरे बताया गया।

कोरबा मेडिकल अस्पताल की ओपीडी में घुसा कोबरा,डॉक्टर की टेबल के नीचे फन फैलाए बैठा मिला

कोरबा। शहर के मेडिकल अस्पताल में मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ओपीडी में डॉक्टर के कंप्यूटर टेबल के नीचे एक जहरीला कोबरा सांप फन फैलाए बैठा मिला। सांप को देखते ही मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी (क्रष्टक्रर) की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू कर कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह डॉक्टर की टेबल के नीचे से फुफ्कारने की आवाज सुनाई दी। कर्मचारियों ने जब टेबल के नीचे देखा तो वहां एक कोबरा फन फैलाकर बैठा हुआ था। जहरीले सांप को देखते ही ओपीडी में मौजूद मरीजों और स्टाफ में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी (क्रष्टक्रर) के अध्यक्ष अविनाश यादव को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक कोबरा को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद टीम ने कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। समय रहते सांप का रेस्क्यू हो जाने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और अस्पताल में मौजूद मरीजों व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन ने भी रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

सभी संचालन क्षेत्रों में एक ही दिन में रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक पौधे लगाने जा रहा है एसईसीएल

- कोल इंडिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभियान के तहत एसईसीएल ने बिलासपुर में एक ही दिन में 15 हजार पौधों का वृहद् वृक्षारोपण
- एसईसीएल द्वारा बिलासपुर शहर में पहली बार मियावाकी पद्धति से वन विकास की पहल

बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 21 जुलाई 2026 को एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने आज बिलासपुर के कोनी स्थित नवीन कमिश्नर कार्यालय के पीछे 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से 15,000 पौधों का वृहद् वृक्षारोपण किया। यह परियोजना संभवत: बिलासपुर शहर की पहली मियावाकी वन परियोजना है, जिसे एसईसीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। मियावाकी तकनीक के माध्यम से विकसित होने वाला यह सघन शहरी वन आने वाले वर्षों में जैव विविधता के संवर्धन, हरित आवरण में वृद्धि तथा स्थानीय पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन, बिलासपुर संभाग के आयुक्त श्री सुनील कुमार जैन, एसईसीएल के निदेशक (एचआर) श्री बिरंची दास, निदेशक (वित्त) श्री डी. सुनील कुमार, सीवीओ श्री हिमांशु जैन, निदेशक तकनीकी (यो./परि.) श्री रमेश चन्द्र महापात्र, कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्री के. राजशेखर, महाप्रबंधक (पर्यावरण) श्री संजय सिन्हा, सहित कंपनी के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा जनभागीदारी के महत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा, पर्यावरण संरक्षण केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मियावाकी पद्धति से विकसित किए जा रहे ऐसे सघन वन न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होंगे, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मेरा युवा भारत कांकेर द्वारा 'विकसित भारत हेतु नशा मुक्ति युवा' जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:-कांकेर 25 जुलाई युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित मेरा युवा भारत , कांकेर द्वारा शनिवार को पीएम श्री शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांकेर में ÷विकसित भारत हेतु नशा मुक्ति युवा÷ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांकेर विधायक आसाराम नेताम थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ÷विकसित भारत 2047÷ के संकल्प को साकार करने में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, नगर पालिका उपाध्यक्ष उत्तम यादव, जनपद पंचायत सदस्य जनता पार्टी शिल्पा साहू, अनूप शर्मा तथा मिंटू तिवारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए युवाओं को अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल आठ विधाओं का आयोजन किया गया। सामूहिक प्रतियोगिताओं नाटक, जबकि एकल प्रतियोगिताओं में चित्रकला, स्लोगन लेखन, रील निर्माण, स्लैम कविता एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाका प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता के परिणामों में रील प्रतियोगिता में मोक्ष संचेती एवं समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में कुमारी निहारिका बिसेन प्रथम रहीं।

चित्रकला प्रतियोगिता में दिलियान्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अर्जुन पटेल विजेता रहे। स्लैम कविता प्रतियोगिता में कुमारी डिकेश्वरी उईके ने प्रथम स्थान हासिल किया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में वैभव शौरी सेजस, चारामा की टीम प्रथम रही। लोकनृत्य प्रतियोगिता में कला मंजरी ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा लोकगीत प्रतियोगिता में अस्मिता पटेल एवं लक्ष्मी पटेल, इच्छापुर प्रथम स्थान पर रहे। आयोजकों ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांकेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित युवाओं को 15 अगस्त के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा, जहाँ उन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करने का अवसर मिल सकता है।

कार्यक्रम का सफल आयोजन मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी सुनील कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आयोजन को सफल बनाने में मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर हर्ष कुमार डोंगरे, अभिषेक रवानी, जितेश नाग, ओम कृष्णा जैन, साथी बोस, नेहाल सिन्हा, अंकित साहू, भूपेंद्र कुंवर, मुकुंद राम, योगेन्द्र कुमार, आदित्य गजीर, कलाम सिंह दुग्गा, अजीत नायक, भूपेंद्र कुमार पटेल, सुब्रत सरकार, आलोक शिकारी, रानु गुप्ता, भावेश साहू, भूमि नागवंशी, देवांश साहू, कोमल यादव, भाविका जुर्री एवं तौषिका प्रधान सहित अन्य स्वयंसेवकों ने विभिन्न व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त समाज के निर्माण एवं विकसित भारत के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सभी युवाओं ने नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

ट्रंप ईरान पर नरम नहीं, पाक ने यूएस से मध्यस्थता का खर्च मांगा; फरवरी से अब तक 59 जहाज आए

वाशिंगटन, एजेंसी। 145 दिनों से जारी जंग के बीच अमेरिका के कई सैनिक बलिदान हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई में ढिलाई बरतने की कोई योजना नहीं है। इसी बीच पाकिस्ता ने ईरान और रु के बीच मध्यस्थता का खर्च मांगा है। लगातार हो रही बमबारी से होर्मुज में उपजे तनाव के बीच फरवरी से अबतक 59 जहाज सुरक्षित भारत आ चुके हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में हमलों की जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान ईरान की उस क्षमता को कम करने के लिए जारी रहेगा, जिससे वह आम नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है। सेंटकॉम ने लिखा, आज शाम 5:30 बजे (पूर्वी समय) से अमेरिकी सेना ने कमांडर इन चीफ के निर्देश पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर और हमले शुरू किए हैं। यह अभियान क्षेत्रीय जल क्षेत्र से गुजरने वाले आम नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करता रहेगा। ये नए हमले ऐसे समय किए गए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को जॉर्जिया में कहा कि ईरान को बहुत बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को 'झड़प' बताया और दावा किया कि तेहरान समझौता करना चाहता है।

ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जो झड़प चल रही है, मैं इसे झड़प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उन्हें बहुत बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है। वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वे अभी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हर बार जब वे समझौता करते हैं तो उसमें बदलाव करना चाहते हैं और सब कुछ बदलना चाहते हैं। वे तैयार नहीं हैं। वे बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे।

अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार, बुशेहर, अहवाज और सीरिक शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के विदेश मंत्री

अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान की रक्षा नीति 'जैसे को तैसा' वाली है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज को निशाना बनाती है तो अमेरिका ईरान के किसी पुल या बिजली संयंत्र पर हमला करेगा। यमन के हूती समूह ने दावा किया कि उसने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक बड़े परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रियाद को नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम संवर्धन की क्षमता विकसित करने की अनुमति मिल सकती है। इस समझौते से दुनिया के नागरिक परमाणु ऊर्जा बाजार में अमेरिका की मजबूत स्थिति फिर से कायम होगी। दोनों देशों का कहना है कि यह समझौता उनके संबंधों को मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही इससे परमाणु सुरक्षा और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इस्राइली सेना की वापसी के एक दिन बाद दक्षिणी शहर जवतर अल-घरबिया का दौरा किया।

संघर्ष के बीच अमेरिका-सऊदी अरब ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब ईरान के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता बता रहा है। उसका कहना है कि यह समझौता आने वाले कई दशकों तक सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर की साझेदारी की नींव तैयार करेगा। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब को परमाणु तकनीक भेज सकेंगी, रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगी और वहां परमाणु ढांचे के निर्माण में मदद कर सकेंगी। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी देश है। वह लंबे समय से इस तरह के परमाणु समझौते की इच्छा रखता था, ताकि अपने बिजली नेटवर्क को मजबूत कर सके।

संक्षिप्त समाचार

नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी आगामी चुनाव जीतती है तो वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाने का अनुरोध करेंगे, ताकि वह वहां के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकें। नवाज शरीफ ने मंगलवार को मुजफ्फराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उनके लिए पंजाब जितना ही प्रिय है। उन्होंने कहा कि यह मेरा दूसरा घर है। मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे। उन्होंने आगे कहा कि यदि पीएमएल-एन चुनाव जीतती है तो वह अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह करेंगे कि उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि वह वहां के विकास कार्यों की स्वयं निगरानी कर सकें। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। नई दिल्ली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में कराए जाने वाले चुनावों का लगातार विरोध करती रही है और वहां की तथाकथित विधानसभाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देती।

समुद्री सीमा पार करते ही कार्रवाई! श्रीलंका ने 9 भारतीय मछुआरे किए गिरफ्तार

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी एक नौका भी जब्त कर ली गई। श्रीलंका की नौसेना ने यह जानकारी दी। नौसेना ने कहा कि ये मछुआरे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार कर तलैमन्नार के उत्तर में स्थित श्रीलंका के जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों के मुद्दे को लेकर जारी तनाव के बीच ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यह मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव का लंबे समय से कारण रहा है। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान में कहा कि बुधवार शाम चलाए गए अभियान के दौरान नौ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। नौसेना के अनुसार, मछली पकड़ने वाली 50 से अधिक भारतीय नौकाओं ने ईरानातीवु के दक्षिण में श्रीलंका के जलक्षेत्र में कथित तौर से अवैध रूप से प्रवेश किया और वहां गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ी जा रही थीं। श्रीलंका की नौसेना ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए नौ भारतीय मछुआरों और जब्त की गई उनकी नौका को कानूनी कार्रवाई के लिए मन्नार के मत्स्य निरीक्षक के हवाले कर दिया गया। इस वर्ष 15 अप्रैल तक कोलंबो के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नौसेना 128 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर चुकी थी और 18 नौकाएं जब्त कर चुकी थी। मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के संबंधों में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। श्रीलंका की नौसेना पर पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने तथा श्रीलंका के जलक्षेत्र में कथित अवैध प्रवेश की कई घटनाओं में उनकी नौकाएं जब्त करने के आरोप भी लगते रहे हैं। पाक जलडमरूमध्य, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है, भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का समृद्ध क्षेत्र है। दोनों देशों के मछुआरे अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण अक्सर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।

ऑपरेशन हार्ड बॉल: ड्रग्स तस्करी मामले में हरमनवीर सिंह गिरफ्तार, रविंदर ढांडा गैंग पर एफबीआई ने कसा शिकंजा

वाशिंगटन, एजेंसी। एफबीआई ने कनाडा स्थित रविंदर ढांडा गिरोह के लिए मादक पदार्थों की तस्करी में कथित भूमिका के लिए भारतीय

नागरिक हरमनवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। एफबीआई ने बुधवार को बताया कि सिंह को मंगलवार को कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।

एफबीआई की यह कार्रवाई ऑपरेशन हार्ड बॉल के बाद हुई, जो लॉरेंस बिश्नोई, जग्गु भगवानपुरिया और रविंदर ढांडा की गिरोहों को लक्षित करने वाली एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन कार्रवाई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि सिंह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में कथित संलिप्तता के लिए वांछित था, जो प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण और वितरण के इरादे से रखने की साजिश और प्रतिबंधित पदार्थों के निर्यात की साजिश में शामिल था।

रविंदर ढांडा पर क्या आरोप है

इसमें कहा गया है कि रविंदर ढांडा संगठित अपराध समूह का मुख्यालय वैंकूवर, कनाडा में है और कथित तौर पर यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों के लिए बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथम्फेटामाइन की तस्करी करता था।

वारंट कब जारी हुआ

23 जून, 2026 को, सिंह के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, क्योंकि उन पर नियंत्रित पदार्थों के वितरण और वितरण के इरादे से कब्जे की साजिश रचने, निर्यात की साजिश रचने और वितरण के इरादे से कब्जे का आरोप लगाया गया था। शुरुआत में एक संयुक्त अभियान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया। जिनमें से 11 कैलिफोर्निया में थे। जो भारत स्थित तीन अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों से जुड़े थे और जिन पर कई आपराधिक कृत्यों का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर, अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत अभियोग में 37 लोगों पर आरोप लगाए थे।

आसियान में रुबियो-लावरोव की अहम मुलाकात आज, यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर फिर होगी बातचीत

मनीला, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो गुरुवार को फिलीपींस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं, जहां उनसे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से मध्यस्थता करने की संभावना को फिर से उठाने की उम्मीद है। रुबियो और लावरोव के बीच यह बैठक दक्षिण-पूर्व एशियाई विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान होने वाली है, जो मनीला में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के आयोजन में क्षेत्र के शीर्ष राजनयिकों की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के मध्यस्थता के प्रयास मंद पड़ गए हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष वार्ताएं रुक गई हैं। ईरान युद्ध मुख्य मुद्दा बन गया है। अंतरिम युद्धविराम समझौते के विफल होने के बाद वाशिंगटन और तेहरान द्वारा नए सिरे से हमले तेज हो गए हैं। रुबियो ने बुधवार

को मनीला में पत्रकारों से कहा कि वह लावरोव के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका इस संघर्ष को समाप्त करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है अगर ऐसा अवसर मिलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ महीनों में इन प्रयासों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या बातचीत को फिर से शुरू करने का कोई अवसर है। रुबियो ने कहा, 'हमें रूसी सरकार के साथ संबंध बनाए रखने होंगे, भले ही हमारे बीच कुछ क्षेत्रों में असहमति हो।' उन्होंने यह भी जिक्र किया कि वे दो सबसे बड़े परमाणु-सशस्त्र देश हैं। आसियान की बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन हालिया बयानों के बारे में रूबियो से पूछेंगे जिनमें उन्होंने भविष्यवाणी की है कि समझौता होने वाला है।

बंधुआ मजदूरी से उत्पाद पर आज आएगी अमेरिकी रिपोर्ट, जद में भारत समेत कितने देश

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका भारत सहित अपने 60 व्यापारिक साझेदार देशों में बंधुआ मजदूरी से तैयार उत्पाद के संबंध में गुरुवार को अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट जारी करेगा। अमेरिका ने इन देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच की थी। यह कदम सभी देशों पर लगाए गए 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की समय-सीमा समाप्त होने से ठीक पहले उठाया जा रहा है। भारत ने इस जांच का विरोध करते हुए कहा था कि इन मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ही चर्चा की जा सकती है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने सीनेट वित्त समिति को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शीर्ष 60 व्यापारिक साझेदारों की ओर से अपनी सीमाओं पर बंधुआ मजदूरी से तैयार सामानों के आयात पर रोक न लगाने या उसे प्रभावी ढंग से लागू न कर पाने की जांच की गई थी। पिछले महीने यूएसटीआर ने

देशों के मौजूदा उपायों की कड़ाई के आधार पर 10 फीसदी और 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। ग्रीर ने बताया कि यूएसटीआर को इस पर 1,600 से अधिक आपत्तियां-टिप्पणियां मिली हैं और 107 गवाहों के साथ दूसरे दौर की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। भारत ने अमेरिका की इस जांच का विरोध किया है। भारत का कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय इन्हें भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फिलहाल बातचीत चल रही है। यूएसटीआर ने यह भी बताया कि अमेरिका एक दर्जन से अधिक देशों में अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमता की भी जांच कर रहा है। हालांकि, इस मामले में अभी शुरुआती निष्कर्ष जारी नहीं किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह जांच उस समय शुरू की थी, जब फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए पारस्परिक शुल्क को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही है।

कड़े मुकाबले में एरिजोना में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में भारतवंशी अमीश शाह जीते

फिनिक्स (एरिजोना), एजेंसी। भारतीय मूल के अमीश शाह ने बुधवार को एरिजोना के एक अहम कांग्रेस (संसद) क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। यह काफी कड़ा मुकाबला था। शाह की जीत से डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी (डीसीसीसी) को झटका लगा है, क्योंकि उसने शाह के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन किया था। यह नतीजा ऐसे समय आया है, जब ज्यादा से ज्यादा मतदाता वाशिंगटन में पार्टी नेताओं की पसंद को खारिज कर रहे हैं।

आपातकालीन चिकित्सक अमीश शाह अब आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार जे फीली का सामना करेंगे। फीली नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के पूर्व खिलाड़ी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी चुनाव में उनका समर्थन किया था। राजनीति में विरोधी बनने से पहले फीली और शाह एक ही टीम न्यूयॉर्क जेट्स का हिस्सा थे। शाह टीम के किनारे तैनात डॉक्टर थे, जबकि फीली टीम के किकर थे। डीसीसीसी ने मार्लीन गैलन-वूड्स का समर्थन किया था। वह पहले रिपब्लिकन पार्टी में थीं और ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई थीं।

क्यों अहम माना जा रहा था यह मुकाबलाा पहले कांग्रेस क्षेत्र के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा था। इस क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी फीनिक्स, स्कॉट्सडेल, फाउंटेन हिल्स और पैराडाइज वैली जैसे समृद्ध इलाके शामिल हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा, इसे तय करने में यह चुनाव भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में रिपब्लिकन मतदाता ज्यादा

हैं, लेकिन पिछले एक दशक में यहां के लोगों की राजनीतिक सोच कुछ हद तक बदली है।

यह सीट खाली हुई है क्योंकि रिपब्लिकन सांसद डेविड श्वाइकर्ट ने गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन मंगलवार को रिपब्लिकन प्राइमरी में वह एंडी बिग्स से हार गए।

मई में जब डीसीसीसी ने गैलन-वूड्स को समर्थन देने का एलान किया, तो डीसीसीसी की अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद सुजान डेलबेनी ने उनके टीवी पत्रकारिता के अनुभव की तारीफ की, लेकिन शाह के बारे में कुछ नहीं कहा।

शाह ने मंगलवार रात समर्थकों से कहा, मैं अपनी पार्टी की पहली पसंद नहीं था। लेकिन मैं पार्टी के स्थापित नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था और यही इस क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं।

हालांकि, शाह ने कहा है कि उम्मीदवार बनने के बाद वह डीसीसीसी के साथ काम करेंगे। उन्हें चुनाव जीतने के लिए पार्टी और उसके दानदाताओं के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि यह मुकाबला मुश्किल माना जा रहा है। इस क्षेत्र में 2024 में ट्रंप को मामूली जीत मिली थी। वहीं, 2020 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से यह क्षेत्र जीता था, जबकि श्वाइकर्ट दोबारा सांसद चुने गए थे। डीसीसीसी के गैलन-वूड्स को समर्थन देने के फैसले से स्थानीय डेमोक्रेट्स हैरान थे। इसकी वजह यह थी कि गैलन-वूड्स और शाह की राजनीतिक सोच में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही बीच की राजनीतिक सोच रखने वाले उम्मीदवार हैं। यह चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ते प्रगतिशील और मध्यमार्गी नेताओं के बीच विवाद का हिस्सा भी नहीं था। यह मुकाबला कुछ हद तक 2024 के चुनाव जैसा था। उस समय शाह ने कई उम्मीदवारों के बीच हुए प्राइमरी मुकाबले में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में गैलन-वूड्स भी शामिल थीं। हालांकि, आम चुनाव में शाह हार गए थे।

ट्रांसजेंडर सैनिकों के इलाज व टेस्टोस्टेरोन नीति में क्या फर्क, जज ने ट्रंप प्रशासन पर उठाए सवाल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की नई टेस्टोस्टेरोन जांच और उपचार पहल पर एक संघीय जज ने सवाल उठाए हैं। जज ने पूछा कि सैनिकों में कम टेस्टोस्टेरोन के उपचार और ट्रांसजेंडर सैनिकों को दिए जाने वाले हार्मोन उपचार में आखिर अंतर क्या है। यह सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर चल रहे मुकदमे के दौरान उठा, जिसमें ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक लगाई गई है। वाशिंगटन की अमेरिकी जिला जज एना रेयेस ने कहा कि ट्रंप की नीति में लिखा है कि सशस्त्र बलों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊंचे मानकों का पालन करना चाहिए। इसके लिए नियमित इलाज या विशेष व्यवस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जज ने मुकदमे से जुड़े दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे बताएं कि ट्रांसजेंडर पुरुषों और अन्य सैनिकों को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने में चिकित्सकीय और व्यावहारिक स्तर पर क्या समानताएं और क्या अंतर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से यह भी जानकारी मांगी कि नई टेस्टोस्टेरोन नीति और ट्रांसजेंडर सैनिकों पर रोक के बीच अलग-अलग व्यवहार का आधार क्या है। रक्षा मंत्री की नई पहल क्या है यह आदेश उस घोषणा के एक सप्ताह बाद आया है, जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सैनिकों की हर साल होने वाली अनिवार्य स्वास्थ्य जांच के दौरान यह जांच भी की जाएगी। 30 वर्ष से कम उम्र के सैनिक अपनी इच्छा से यह जांच करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में हेगसेथ ने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। ट्रंप प्रशासन के दूसरे अधिकारी भी पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन उपचार को आसान बनाने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस विषय पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, जिनके पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होता है।

अमेरिका के मैडिसन में पुलिस पर फायरिंग

गिरफ्तारी के दौरान अधिकारी पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में आरोपी ढेर

मैडिसन, एजेंसी। मैडिसन के एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि पीड़ित ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस को चाकू से घायल कर दिया था। यह जानकारी शहर के पुलिस प्रमुख ने दी। घटना के तुरंत बाद गोलीबारी का मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में तीन गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। मैडिसन पुलिस प्रमुख जॉन पैटरसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि प्रसारित हो रहा फुटेज घटना का सिर्फ एक पहलू है। पैटरसन ने कहा 'मैं इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पैटरसन ने बताया कि मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, लेकिन पुलिस ने उसका नाम जारी नहीं किया। यह गोलीबारी राज्य की राजधानी से दो मील से भी कम दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय इलाके की सड़क पर हुई, जहां रेस्तरां, बार, दुकानें और आवासीय मकानों की भरमार है। घटना के फुटेज में चौराहे पर कई कारें रुकी हुई दिखाई दे रही हैं और

लोग घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2015 में, उसी सड़क पर एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने टोनी रॉबिन्सन, जो मिश्रित नस्ल के थे उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिला अटॉर्नी ने उस घटना में पुलिस के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अधिकारी की कार्रवाई को उचित ठहराया था। बुधवार को गोली चलाने वाले अधिकारी और गोली लगने से मारे गए व्यक्ति की नस्ल के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी जारी नहीं की। लेकिन मैडिसन में अश्वेत समुदाय के समर्थकों ने कहा कि मरने वाला व्यक्ति अश्वेत था। मैडिसन स्थित अश्वेत समुदाय के हिमायती समूह अर्बन ट्रायज की प्रमुख ब्रांडी ग्रेसन ने कहा 'मैडिसन की एक सड़क पर एक और अश्वेत व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे समुदाय ने उसका नाम जानने से पहले ही उसे मरते हुए देखा। यह राज्य हिंसा की क्रूरता है।' पैटर्सन ने बताया कि पुलिस को पड़ोस में खड़ी गाड़ियों में घुसने की कोशिश करने की सूचना मिली थी। पैटर्सन ने बताया कि संदिग्ध पुलिस अधिकारियों के सड़क पर संपर्क करने से पहले पास के पिछे से होते हुए बाइक पर भाग निकला। पैटर्सन ने बताया कि संदिग्ध या तो अपनी बाइक से गिर गया या अधिकारियों ने उसे बाइक से नीचे उतारा और हाथापाई के दौरान उसने चाकू निकालकर एक अधिकारी को घायल कर दिया।

60 साल से जमीन पर काबिज बंगाली परिवारों ने मांगा मालिकाना हक

विधायक किरण देव को सौंपा ज्ञापन, भूमि की रजिस्ट्री और भूमिस्वामी अधिकार देने की उठाई मांग

जगदलपुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। दंडकारण्य परियोजना के तहत बस्तर में बसाए गए बंगाली विस्थापित परिवारों ने एक बार फिर अपनी वर्षों पुरानी भूमि अधिकार की मांग उठाई है। निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति और बंगाली समाज राष्ट्रीय संगठन, बस्तर संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मुलाकात कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आबंटित कृषि और आवासीय भूमि की रजिस्ट्री कर भूमिस्वामी अधिकार देने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से आए विस्थापित परिवारों को दंडकारण्य विकास प्राधिकरण (डीडीए) के माध्यम से बस्तर में बसाया गया था। पिछले करीब छह दशक से ये परिवार उन्हीं जमीनों पर खेती और निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का वैधानिक स्वामित्व नहीं मिल सका है। इसके चलते रजिस्ट्री, डायवर्सन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300ए का हवाला देते हुए आबंटित भूमि की कानूनी स्थिति का परीक्षण कराने और पात्र परिवारों को भूमिस्वामी अधिकार देने की मांग की। साथ ही राज्य शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया।

विधायक किरण सिंह देव ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया और मामले को शासन के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि विषय का परीक्षण कर नियमानुसार समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने विधायक के आश्वासन के बाद उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित भूमि अधिकार का मुद्दा अब समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा।मुलाकात के दौरान संभागीय अध्यक्ष जीवानंद हालदार, महासचिव श्याम घोष, सह सचिव प्रदीप गुहा, मीडिया प्रभारी मृण्मय बारोई, अनिमेष पाल, गोपाल मालिक, राकेश हालदार, मोनी डे, दिलीप गुहा, तपन दत्ता, बिजन विश्वास, मिंटू सहित बंगाली समाज के अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

धरपूरा में न्यू जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ फाउंडेशन की बैठक सम्पन्न, संगठन को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन

धरपूरा /मूक पत्रिका

धरपूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में न्यू जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों सहित ब्लॉक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और संगठन के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में संगठन के विस्तार, मजबूती और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन और आपसी समन्वय में निहित है। सभी सदस्यों से अपने दायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर संगठन के विस्तार के लिए अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ने, पत्रकारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा करने, सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने तथा जनहित के विषयों पर सशक्त भूमिका निभाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि संगठन को गांव-गांव और शहर-शहर तक मजबूत करने के उद्देश्य से नियमित बैठकें एवं जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे।बैठक का समापन संगठन की एकजुटता, पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और पत्रकार हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में प्रदेश सचिव श्याम दीवान, प्रदेश संगठन मंत्री पवन कुमार नाग, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष जयशंकर पांडे, तुलसीराम ठाकुर, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बाईक में 30 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ाया आरोपी

जिला उड़नदस्ता टीम की कार्यवाही से हिरासत में आरोपी

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

आबकारी आयुक्त पी एस एल्मा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पदमिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा गवाहों की उपस्थिति में भकुर्रा अमलीडीपा मार्ग पर संदिग्ध वाहनो की विधिवत जाँच तलाशी लेकर अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।वाहनों की तलाशी के दौरान ग्राम भीमसेनडीह निवासी आरोपी ललित जायसवाल पिता सहदेव के दोपहिया वाहन बजाज प्लेटिना ऋमांकष्ट्ठ 13 ,र 2154 में 30 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब पर वाहन जप्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 (क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराया गया। इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

अनुमानित मीटर रीडिंग से बढ़ रहे बिजली बिल, उपभोक्त I परेशानः जिम्मेदारी किसकी–विभाग, ठेकेदार या ठेका कर्मचारी?

घरघोड़ा/रायगढ/मूक पत्रिका

क्षेत्र में कई बिजली उपभोक्ता इन दिनों आवश्यकता से कहीं अधिक बिजली बिल आने की समस्या से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे नियमित रूप से हर माह लगभग 400ङ्क500 रुपये का बिजली बिल जमा करते रहे, लेकिन अचानक कई महीनों का समायोजन (स्नद्धह्वह्यह्लद्वद्गठ्ठह्ल) होने के बाद 40 से 50 हजार रुपये तक का बिल जारी कर दिया गया। ऐसे भारी-भरकम बिलों ने आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाला है।जानकारों के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग प्रत्येक बिलिंग चक्र में वास्तविक रूप से ली जानी चाहिए, ताकि उसी के आधार पर सही बिल जारी हो। लेकिन कई स्थानों पर मीटर रीडिंग का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। आरोप है कि कुछ मामलों में ठेका कर्मचारी कई महीनों तक मौके पर जाकर वास्तविक रीडिंग लेने के बजाय अनुमानित (1द्गह्लड्डद्द/क्क्रश्1द्बह्यद्बश्ठ्ठड्डद्य) रीडिंग भेज देते हैं। इसके आधार पर विभाग बिल जारी करता रहता है। बाद में जब वास्तविक रीडिंग ली जाती है, तब कई महीनों की खपत एक साथ जुड़कर उपभोक्ता के नाम भारी राशि का बिल जारी हो जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वास्तविक मीटर रीडिंग समय पर नहीं ली गई और विभाग ने अनुमानित रीडिंग के आधार पर लगातार बिल जारी किए, तो इसकी जिम्मेदारी केवल उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती। मीटर रीडिंग कराने, उसकी निगरानी करने तथा सही बिल जारी करने की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्युत वितरण कंपनी की होती है। यदि रीडिंग का कार्य ठेकेदार को सौंपा गया है, तब भी अंतिम प्रशासनिक उत्तरदायित्व विभाग का ही रहता है, जबकि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और उसके कर्मचारी भी जवाबदेह हो सकते हैं।

उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में विभाग को प्रत्येक मामले की जांच कर वास्तविक खपत के आधार पर बिल का परीक्षण करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी या एजेंसी की लापरवाही के कारण उपभोक्ता पर एकमुश्त हजारों रुपये का बोझ पड़ा है, तो उसके समाधान के लिए किस्तों में भुगतान, बिल की जांच तथा आवश्यक सुधार जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।बिजली उपभोक्ताओं ने मांग की है कि प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से वास्तविक मीटर रीडिंग सुनिश्चित की जाए, अनुमानित बिलिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगे तथा लापरवाही करने वाले संबंधित कर्मचारियों और एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

वारंटी में भी वसूली? रायगढ़ के अपराजिता ज्ज्ड्क्स शोरूम पर ग्राहक का गंभीर आरोप !

रायगढ़/मूक पत्रिका

चार महीने पुरानी झ्ङ्कस् द्बह्नह्वड्ढद्ग श्व-स्कूटी में तकनीकी खराबी आने पर सर्विस सेंटर पहुंची गाड़ी, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि वारंटी अवधि होने के बावजूद लेबर चार्ज के नाम पर ?364 का बिल थमा दिया गया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर कहा गया कि ÷लेबर चार्ज दिए बिना गाड़ी नहीं मिलेगी।÷अब असंतुष्ट ग्राहक ने मामले को उपभोक्ता फोरम तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप भी नई बाइक, स्कूटी या श्व-स्कूटी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें और अपने उपभोक्ता अधिकारों को समझें।

15 साल से है पुल बनने का इंतजार , उफनते नाले को पार कर अपने स्कूल पहुंचने को विवश हैं स्कूली बच्चे

धरमजयगढ़ / रायगढ़/मूक पत्रिका

=छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बच्चों की पढ़ाई की राह खतरों से भरी हुई है। धरमजयगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत क्रोंधा के लगभग 50 छात्र-छात्राएं हर दिन उफनते नाले को पार कर खड़गांव स्थित अपने स्कूल पहुंचने को विवश हैं। बारिश के मौसम में नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चे घुटनों से ऊपर बहते पानी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हाल ही में एक छात्रा तेज बहाव में बहने लगी थी, जिसे उसके साथ जा रहे बच्चों ने बड़ी मुश्किल से खींचकर बचाया।

साइकिल किनारे छोड़ी और पैदल नाला पार किया

क्रोंधा से खड़गांव स्कूल का सफर बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। छात्र सबसे पहले अपनी साइकिल से नाले के तट तक आते हैं। फिर साइकिल को किनारे खड़ी कर पानी के बीच से गुजरते हैं। इसके बाद उन्हें करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है।

बड़ा हादसा टला

छात्राओं ने बताया कि कुछ दिन पहले नाला पार करते वक्त एक बच्ची पानी की धार में बहने लगी थी। सहपाठियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे किसी तरह सुरक्षित निकाला। स्कूली बच्चों के अलावा सामान्य ग्रामीणों और मरीजों के लिए भी यह रास्ता मुसीबत बन जाता है। बारिश में जलस्तर बढ़ते ही गांव का संपर्क कट जाता है।

वर्ष 2015 से सिर्फ मिल रहे आश्वासन

स्थानीय लोग वर्षों से इस सरिया नाले पर पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2015 में जब विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री थे, तब भी उन्होंने पुल निर्माण का भरोसा दिया था। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ओर से पुल की घोषणा हुई, मगर धरातल पर काम शुरू नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के चक्कर काटकर अब ग्रामीण थक चुके हैं।प्रभारी प्राचार्य नियमेश कुमार पटेल का बयान=क्रोंधा से लगभग 50 बच्चे हमारे स्कूल आते हैं। नाले में पानी ज्यादा होने पर वे स्कूल नहीं आ पाते। कई बार बच्चों को साथ में अतिरिक्त कपड़े (यूनिफॉर्म) रखने पड़ते हैं।सरपंच राम रतन सिंह राठिया का बयान =गांव के लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए खड़गांव जाना पड़ता है। तत्कालीन सांसद से दो बार आश्वासन मिला था। अब उनके मुख्यमंत्री बनने से उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

सेतु विभाग ने भेजा 10 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव

प्रशासनिक उदासीनता से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। इस बीच लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग ने मामले में प्रगति की जानकारी दी है।

सेतु विभाग के कार्यपालन अभियंता (श्वश्व) संतोष कुमार भगत ने बताया कि क्रोंधा से खड़गांव के बीच स्थित सरिया नाले पर उच्च स्तरीय पुल (High-Level Bridge) के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। प्रस्तावित पुल की लंबाई 105 मीटर होगी और इसके निर्माण पर 10 करोड़ 17 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी। प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ढाई वर्ष के कार्यकाल की सराहना, कलेक्टर ने सुरक्षा और विकास में योगदान को बताया उल्लेखनीय

बीजापुर के एसपी डॉ. जितेंद्र यादव को भावभीनी विदाई

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले में लगभग ढाई वर्ष तक पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद कबीरधाम स्थानांतरित हुए डॉ. जितेंद्र यादव को शनिवार को जिला प्रशासन ने भावभीनी विदाई दी। जिला कार्यालय के इंद्रावती सभाकक्ष में आयोजित समारोह में कलेक्टर विश्वदीप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए सम्मानित किया।कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि नक्सल प्रभावित बीजापुर में डॉ. यादव के कार्यकाल के दौरान पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। इससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि डॉ. यादव ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी नेतृत्व का परिचय दिया और जिले में जनविश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप संचालक संदीप बलगा, वनमंडलाधिकारी डॉ. जाधव सागर, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, आईपीएस अधिकारी रविंद्र मीणा तथा अमन कुमार झा सहित अन्य अधिकारियों ने भी डॉ. यादव के साथ कार्य करने के अनुभव साझा किए और उनके नेतृत्व एवं कार्यशैली की सराहना की। अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र यादव ने कहा कि बीजापुर में बिताया गया समय उनके जीवन का अविस्मरणीय अध्याय रहेगा। उन्होंने जिले में मिली उपलब्धियों का श्रेय जिला प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों को देते हुए कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करने से जिले में शांति और विकास का वातावरण मजबूत हुआ है। समारोह में अपर कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल, सीएमएचओ डॉ. बी.आर. पुजारी, संयुक्त कलेक्टर उत्तम पंचारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में डॉ. यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।